TITLE CODE : UPHIN49731

राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका

बसावन इंडिया

वर्ष : 2, अंक : 07 आजमगढ़ • जनवरी 2023 • मूल्य : ₹30

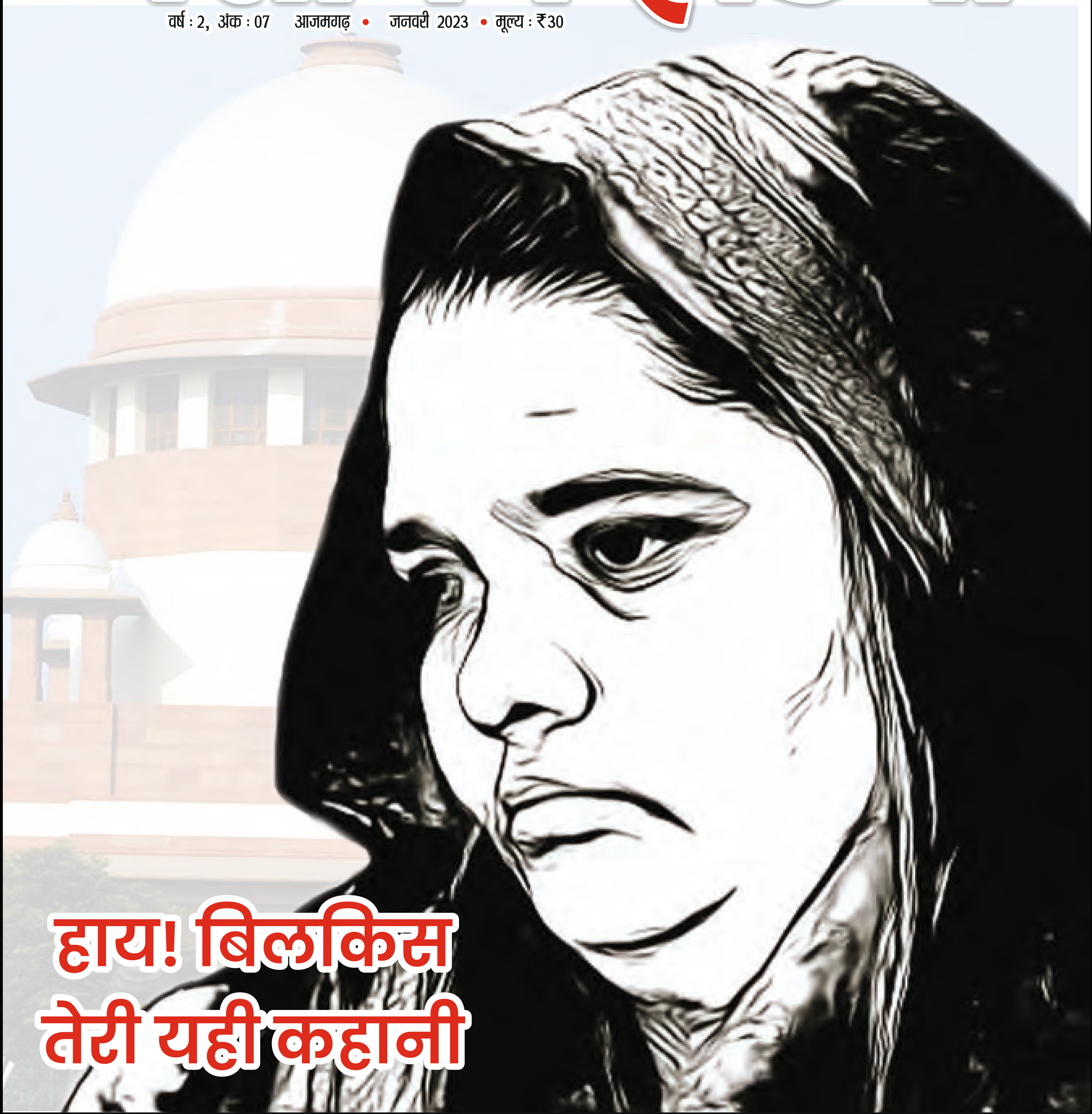

हाय! बिलकिस तेरी यही कहानी

बुद्धं शरणं गच्छामि

सदियों में पैदा होता है तुझसा कोई शख्स मुलायम

सुप्रीम कोर्ट का 15 बनाम 85

संपादकीय

मिलीमार और तकरार के बीच निकलेगी बसावट की लड़ाई

इक्कीसवीं सदी का 22वां साल जाते-जाते क्या क्या सिखा गया| मानवता के बसने-उजड़ने की तमाम कहानियां मानव की जयगाथा को बयां कर रहीं हैं| ऐसे में यूनिवर्स के एक गोले, जिसे हम धरती कहते हैं, और जहाँ भारत बसता है, वहाँ 2022 समता की लडाई और उसे बनाने-बसाने की जद्दोजहद के रूप में देखा जाना चाहिए| जिधर भी नजर उठाइए, कुछ चल रहा है, कुछ जल रहा है, कुछ खल रहा है, तो कुछ पता नही चल रहा है कि क्या हो रहा है? इसे समझाने के लिए 3-4 बातों का जिक्र जो सोचने की मजबूर कर रही हैं|

बिलकिस बानो के साथ जो हुआ, उसे पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसके आरोपियों को जिस तरीके से छोड़ा गया और जिस तरीके से दुनिया के सामने प्रदर्शित किया गया, उसपर रुक कर, ठहर कर, देखने-समझने की जरुरत है, क्या भारत में इस तरह का न्याय होने जा रहा है? ऐसे में हजारों जातियों में बटें समाज में जहाँ न्याय की आधुनिक अवधारणा अभी तक ठीक से पढ़ी- पढ़ाई नही गई, इससे न्यायिक संस्थाओं और लोकतान्त्रिक संस्थाओं के प्रति मोहभंग होना शुरू हो जाएगा| बिलकिस का महिला होना या मुसलमान होना, से ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत का नागरिक होना| भारत का संविधान हर नागरिक को समता, समान अधिकार, समान अवसर की बात करता है लेकिन खुलेआम संविधान की भावनाओं को तार-तार किये जाने पर ऊपर से चुप्पी भले रही हो,लेकिन अंडर करंट बहुत तगड़ा दिखा, जिसे सोशल मीडिया पर देखा-सुना जा सका। ये अंडर करंट विविध रूपों में विभिन्न घटनाओं को लेकर दिखा| जातीय अन्याय से पीड़ित लोगों में गुस्से का इज़हार पूरे देश में दिखा|ये बेकरारी लोगों को यहाँ तक ले जा रही है, कि बड़ी संख्या में लोग धर्म- परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहे हैं| यह परिवर्तन अब शोर शराबे आयोजन के साथ सामने आ रहा है| बड़ी संख्या में लोग बौद्ध , इसाई और कहीं-कहीं इस्लाम की ओर बढ़ रहे हैं| धर्म को मानने, स्वीकार करने और उसके आचरण की पूरी आज़ादी भारत के संविधान में है, पर प्रतिक्रियावादी ताकतें, कई बार इसे लालच और प्रलोभन का आरोप लगाने से लेकर – लड़ाई झगड़े के लिए आगे आ रही हैं विशेष कर आदिवासी इलाकों में धर्म-परिवतन को लेकर लड़ाई-झगड़े और मामला पुलिस के हस्तक्षेप तक जा रहा है| ऐसे में आने वाले समय में देश की लोकतान्त्रिक संस्थाओं के सामने ये बड़ी चुनौती है कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कैसे की जाए और लोगों को प्रदत्त अधिकारों की रक्षा कैसे हो ? इसपर अच्छी बात यह है कि मुख्यधारा की मीडिया, राजनीतिक दलों से लेकर विमर्श पैदा करने वाली संस्थाएं भले ही चुप्पी बनाए रखीं या केवल देखती रही लेकिन सोशल मीडिया से लेकर सामाजिक न्याय की चिंता करने वालों ने इसपर खूब लिखा और बोला।

2022 का साल इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि सामाजिक न्याय के प्रति सरकार के संस्थानों विशेषकर न्यायपालिका की भूमिका पर कैसे सवाल खड़े हुए? विशेषकर आरक्षण सम्बन्धी फैसलों को लेकर ! 10 प्रतिशत सवर्णों के आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर इस आधार पर भी सवाल उठे कि सवर्णों पर फैसला और सारे जज सवर्ण, जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है | पूरी दुनिया में लोकतान्त्रिक संस्थानों के विकास के दौरान कुलीन व्यवस्था से आगे बढ़ते हुए विविधता यानी सबकी भागीदारी निरंतर बदली गई| 2022 का साल इस विविधता पर विभिन्न तरीके से लड़ी गई लड़ाइयों और बहस को लेकर याद किया जाएगा | विश्वविद्यालयों , शिक्षण संस्थाओं के उच्च पदों और मीडिया में कुछ जातियों (धर्म नही) का वर्चस्व पर लगातार सवाल उठे और उनको लेकर सर्वोच्च न्यायालय की कोलोजियम व्यवस्था को लेकर मुख्य न्यायाधीश तक बचाव की मुद्रा में दिखे, वहीं जो सवर्ण आरक्षण को लेकर कोई आँकड़ा नहीं मांगी, कई राज्यों में ओबीसी के आरक्षण पर आँकड़े ही आँकड़े मांगते जा रहे हैं। हद तो तब दिखी जब छत्तीसगढ़ में अभी तक सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा था जबकि उनकी आबादी का सर्वेक्षण 3 प्रतिशत के आस-पास आया।

फिलहाल 2022 का साल जाते-जाते कई चीजों पर चिंताएं दे गया है जिनपर आने वाले साल में घनघोर विमर्ष होना है, जो 2024 के लोकतंत्र के चुनाव में पीक पर होगा।

नये वर्ष की शुभकामनाओं के साथ...

नरेन्द्र

TITLE CODE : UPHIN49731
आज़मगढ़ (उ.प्र.) ▪ माह - जनवरी
सन् - 2023 ▪ वर्ष - 2 अंक - 07

बसावन इंडिया

संपादक
नरेन्द्र प्रताप

सह-संपादक
डॉ. नरेश कुमार साहू

प्रबंध संपादक
अरविंद कुमार यादव

कंटेंट एडिटर
डॉ. प्रमोद कुमार, विक्रमजीत, बिनिका दुर्गम, कमलेश यादव मैत्रेयी सिंह

ब्यूरो प्रमुख
दिल्ली एनसीआर - परिभाषा
लखनऊ - देशराज (एडवोकेट)
छत्तीसगढ़ - डॉ. जितेन्द्र सोनकर
मध्यप्रदेश - तेजबहादुर
महाराष्ट्र - अकाश खोब्रागड़े
राजस्थान - डॉ. कालूलाल कुलमी
प्रयागराज - धैर्य मित्र सिंह
कुशीनगर - कोमल प्रसाद
वाराणसी - विजय कुमार
बलिया - विनय कुमार
देवरिया - डॉ. सुनील कुमार
गोरखपुर - डॉ. विरेन्द्र कुमार
सरगुजा संभाग - कृष्णा पैकरा

विधिक सलाहकार
अमरजीत चक्रवर्ती
रविशंकर यादव

डिजाइन एंड ले-आउट
इरफान खान - +91 93299 60007

संपादकीय कार्यालय
31 शहीद द्वारा, आजमगढ़,
उत्तर प्रदेश पिन- 276 001
Email : basavanindia@gmail.com
www.facebook//बसावन इंडिया
+91 9453171770

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी नरेन्द्र प्रताप द्वारा मेट्रो प्रिंटर्स, डी 102, महानगर एक्सटेंशन, लखनऊ, (उ.प्र.) से मुद्रित व तथागत शहीद द्वारा सिविल लाइन, आजमगढ़ (उ.प्र.), पिन-276 001 से प्रकाशित

इस अंक की झलकियां

हाय! बिलकिस तेरी यही कहानी	2
कॉलेजियम पर कोलाहल	6
प्रमोशन में ओबीसी को आरक्षण दिए जाने की मांग	10
घटना चक्र : 2022 की 22 घटनाएं	16
जातीय जनगणना रिपोर्ट ग्राम सभा- छिड़ा, जिला- अमेठी	24
यूपी के विश्वविद्यालयों में सवर्ण कुलपतियों का बोलबाला	25
इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय में चार सौ फीसदी फीस वृद्धि	27
भाजपा के नहले पर भूपेश का दहला	29
सुल्तानपुर : सामाजिक न्याय की नई उर्वर भूमि	30
अनुसंधान केवल थीसिस या पुस्तक के रूप में केवल पुस्तकालय का हिस्सा नहीं होना चाहिए	32
नशे की गिरफ्त में आदिवासी समाज	33

www.theforthstate.in
बसावन इंडिया के आर्टिकल्स द फोर्थ स्टेट डॉट इन पर भी पढ़े जा सकते हैं।

08 **जेएनयू की पिंक दिवारों पर नफ़रत के लाल छींटे** - दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूनिवर्सिटी JNU का एक बार फिर से सुर्ख़ियों में है। इस बार हिंदू-मुस्लिम

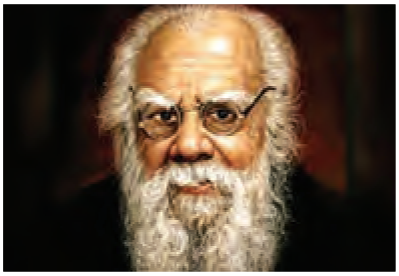

11 **पेरियार मय होता भारत... उत्तर भारत में पेरियार का जलवा** - उत्तर भारत में आत्मसम्मान आंदोलन के जनक पेरियार रामास्वामी नायकर का...

14 **बुद्धं शरणं गच्छामि** - दिल्ली के करोल बाग स्थित अंबेडकर भवन में अशोक विजयदशमी के दिन देश के कोने कोने से और दिल्ली व आस...

21 **सदियों में पैदा होता है तुझसा कोई शख़्स मुलायम** - हाल के दिनों में भारत और पड़ोसी देश चीन के बीच जिस तरह के हालात बने।...

इस अंक में प्रकाशित सामग्री के आंशिक या पूर्ण रुप से पुनर्प्रकाशन के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य है। लेखक के विचार व्यक्तिगत हैं। प्रकशित सामग्री में दिए गए तथ्य संबंधी विवादों का पूर्ण दायित्व लेखक का है। संपादक, मुद्रक, प्रकाशक एवं सहयोगी संपादकीय टीम इसके लिए हरगिज उत्तरदायी नहीं होंगे। किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान हेतु न्याय क्षेत्र आजमगढ़ होगा।

हाय ! बिलकिस तेरी यही कहानी

जिस समय हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो तथा देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली के लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नारी सम्मान तथा नारी अस्मिता को लेकर गंभीर चिंता जाहिर कर रहे थे ऐसे समय उन्ही के गृहराज्य गुजरात में कुछ ऐसी घटना घट रही थी जो देश के रूप में भारत वर्ष को शर्मिंदा तो कर रही थी , बल्कि इंसानियत को भी तार तार कर रही थी, वह घटना बिलकिस बानो के गुनाहगारों को ससम्मान सजा से मुक्त कर कारावास से मुक्त करना। उनका स्वागत ऐसे किया जा रहा था जैसे कि जंग फतह कर लौटे हों।

▪ **कमलेश यादव**

यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी क्योंकि, इसमें आरोपियों द्वारा एक ऐसी जघंयतम घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें बिलकिस बानों एक तीन वर्षीय बच्ची को पटक-पटक कर मार दिया गया था, साथ ही घर के सदस्यों को भी मौत के घाट उतर दिया गया था। बिलकिस बानो के साथ बलात्कार किया गया जो कि उस समय तीन महीने की गर्भवती भी थी। यह घटना 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में कर सेवकों के जिन्दा जाला दिए जाने के फलस्वरूप गुजरात में सांप्रदायिक दंगों में हुआ था।

जैसा कि हर समय सांप्रदायिक दंगों में होता रहा है कि निर्दोष नागरिक ही पीड़ित होते हैं ऐसा ही गुजरात दंगों में बिलकिस बानों के साथ हुआ। इस केस में एक लम्बी कानूनी प्रक्रिया में आरोपियों को दोषी पाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी जिस पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी

देश के नाम बिलकिस का ख़त

15 अगस्त 2022 को मुझ पर जैसे पिछले 20 वर्षों का सदमा फिर से कहर की तरह टूट पड़ा जब मैंने सुना कि जिन 11 आरोपियों ने मेरा जीवन नष्ट किया मेरी आँखों के सामने मेरे पूरे परिवार को ख़त्म किया मेरी तीन साल की बेटी मुझसे छीन ली वो सभी रिहा कर दिए गए। उनका वो आह्लाद (खुश हो कर) घूम रहे हैं। ये सुनने के बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मै शून्य और खामोश सी हो गयी हूँ। मैं केवल इतना कह सकती हूँ क्या एक औरत को दिए गए न्याय का अंत यही है? मैंने इस देश के सबसे ऊँचे न्यायालय पर विश्वास रखा, मैंने इस व्यवस्था पर विश्वास रखा, मै धीरे-धीरे अपने सदमे के साथ जीना सीख रही थी लेकिन इन 11 आरोपियों कि रिहाई ने मुझसे मेरी शांति छीन ली और न्याय की व्यवस्था से मेरा भरोसा उठ गया। मेरा दुःख और डगमगाता मेरा विश्वास उन सब औरतों के लिए है जो इंसाफ की तलब में अदालतों की लडाई लड़ रही हैं।

इन आरोपियों को रिहा करने के अभूतपूर्व फैसले से पहले किसी ने हमसे नहीं पूछा, मेरी सुरक्षा बहाली के बारे में नहीं सोचा। मैं गुजरात सरकार से अपील करती हूँ कि इस हानिकारक फैसले को वापस ले और शांति से निडर होकर जीने का अधिकार मुझे वापस लौटाए और मेरे परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करे।

अपनी मुहर लगाई। हम इस केस की प्रक्रिया कैसे चली? कैसे गुजरात के बाहर महाराष्ट्र में स्थान्तरित किया गया? अपराधियों को कैसे सजा मिली इस पर चर्चा न कर वर्तमान प्रसंग पर ही रहना चाहते हैं जिसमें एक राज्य द्वारा आरोपियों को बरी करना है।

गुजरात सरकार के इस फैसले से सभ्य तथा जागरूक समाज हतप्रभ तथा निराश है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जघंयतम अपराध के दोषियों को मुक्त किया गया जो समाज के खतरा तो हैं ही बल्कि उससे ज्यादा बिलकिस बानो के लिए जो पहले से ही बुरी मानसिक प्रताड़ना में थी। अब तो उनका जीवन ही खतरे में है जैसा कि दोषियों के मुक्त किये जाने के बाद बिलकिस बानों ने देश के नाम एक भावनात्मक ख़त अपने वकील के मार्फ़त सार्वजनिक किया।

सबसे शर्मनाक हरकते

बिलकिस बानो के इन गुनाहगारों को मुक्त करने के पश्चात् सबसे शर्मनाक उनके स्वागत का रहा। माला पहनाकर, उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेना। इतना ही नहीं इन गुनाहगारों के बारे में गोधरा के भाजपा विधायक सी के टाइल का बयान आश्चर्य चकित करने वाला था जिसमें उन्होंने ने कहा कि वे ब्राहमण हैं, संस्कारी हैं। मनुवादी मानसिकता से ग्रसित विधायक जी शायद यह भूल गये कि आज देश मनु के क़ानून से नहीं डॉ. भीम राव अम्बेड़कर के संविधान से चलता है।

दोषियों के रिहाई के पश्चात् देश में जैसी प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए ऐसी प्रतिक्रियाओं के विपरीत कुछ भी नहीं हुआ। लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ में मुख्य धारा के मीडिया की कोई प्रतिक्रिया भी नहीं रही। कुछ सोशल साईट के स्वतंत्र पत्रकारों को छोड़कर तथा राजनीतिक पार्टियों में इस पर लगभग मौन रही। ऐसे में एक समाज एक देश के रूप में यह अत्यंत चिंता का विषय है जहाँ पर नागरिक समाज अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करता।

वहीं 2013 में दिल्ली में निर्भया कांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। जिससे देश का नागरिक समाज, विपक्षी राजनीतिक पार्टियों तथा मीडिया ने सरकार के खिलाफ आंदोलन कर, सरकार पर दबाव डालकर कानून में बदलाव करवाकर दोषियों को सजा दिलवाई। वही हमारे देश में 2014 के बाद ऐसे मामलों में एक बदलाव सा नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना (कठुआ कांड) के बाद हिंदू मुस्लिम का एंगिल प्रवेश करा के बलात्कारियों के समर्थन में तत्कालीन जम्मू कश्मीर के मंत्री के द्वारा तिरंगा यात्रा का निकला जाना लेकिन कठुआ कांड में न्याय की जीत हुई।

ऐसे में बिलकिस बानो के दोषियों को मुक्त कर गुजरात सरकार ने कहीं न कहीं हिंदू-मुस्लिम करने के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि बीते साल के अंत में गुजरात विधानसभा का चुनाव होना था। जिसमें भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रही थी, 2024 में केंद्र सरकार के लिए भी चुनाव होने हैं राज्य में भाजपा सरकार होने पर केंद्र के लिए जीत आसान होगी। ऐसे में क्या नागरिक समाज अपने अधिकार तथा सामाजिक न्याय को सरकार के हाथ में गिरवी रख देगा जिससे राजनीतिक पार्टियों जैसे चाहे वैसे जनता के नागरिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ करती रहे तथा संविधान की धज्जियां उड़ाती रहें!

भेदभाव पूर्ण दण्ड संहिता के श्रोत कहां-कहां है -

स्मृतियां तथा पुराण भारतीय हिन्दू समाज व्यवस्था के कोड ऑफ कन्डक्ट रहे है। उनके अनुसार ही न्याय व्यवस्था चलती रही। इनमें वर्णित भेदभाव पूर्ण व्यवस्थाओं को नीचे दर्शाया गया

- “ब्राह्मण अवध्य है, इसीलिए उसके केश मुड़वा दें और अन्य वर्ण वालों को प्राण दंड दें।” -(मनुस्मृति, 8-379)
- “ब्राह्मण को प्राण दंड होने पर उसका मुंडन करा देना ही उसका प्राण दंड होता है तथा अन्य वर्णों का (क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) का प्राण-दंड प्राण नाश करना होता है।” -(मनुस्मृति, 8-369)
- “किसी प्रकार का भी पाप करने पर ब्राह्मण को कभी न मारें और सम्पूर्ण धन तथा अभग्न शरीर सहित देश से निकाल दें।” -(मनुस्मृति, 8-380)
- “ब्राह्मण के वध से अधिक अन्य कोई पाप संसार में नहीं है। इसलिए राजा उसको मारने का विचार न करे।” -(मनुस्मृति, 8-382)
- “वैसे ही ब्राह्मण चाहे मूर्ख या विद्वान हो, वह महान देवता होता है। वेद विधि से प्रतिष्ठित हो या न हो, जैसे अग्नि महान देव है। “ -(मनुस्मृति, 9-317)
- ‘इस प्रकार ब्राह्मण यदि बुरा कार्य भी करे तो भी पूजनीय है। क्योंकि वह भू-मंडल में परम् देवता है।” -(मनुस्मृति, 9-319)
- “ब्राह्मण दुष्चरित्र भी हो तो भी पूज्यनीय है। शूद्र जितेन्द्रिय होकर नहीं। क्योंकि ऐसा कौन होगा जो दुष्ट गाय को छोड़कर सुशील गधी को दुहेगा।” -(पाराशर स्मृति 8-33)
- “राजा ब्राह्मण को छोड़कर सबका शासक है।” -(गौतम धर्म सूत्र 8-15-11-59)
- “ब्राह्मण को तृण से ताड़ना करने, उसके कंठ में वस्त्र डालने अथवा विवाद में उसे जीत लेने पर भी प्रणाम द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। ब्राह्मण को वध की धमकी देने पर सौ वर्ष पर्यन्त तथा दण्ड प्रहार से हजार वर्ष पर्यन्त नरक में रहना होता है। धरती पर गिरा हुआ ब्राह्मण का रक्त धूलि में जितने कणों को गिराता है उतने हजार वर्षों तक वह रक्त गिराने वाले नरक में वास करता है।” -(मनुस्मृतिष 11-205-207)
- “यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को गाली दे तो सौ कर्षपण दंड दे। यदि ब्राह्मण को मारे, तो इससे दुगुना दंड दे। यदि वैश्य ब्राह्मण को गाली दे तो क्षत्रिय से डेढ़ गुना दंड दे। परन्तु यदि ब्राह्मण क्षत्रिय को गाली दे तो केवल पचास कर्षपण दण्ड दे। यदि वैश्य को गाली दे तो उसका आधा दंड दे और शूद्र को गाली देने का कोई दंड नहीं है।” -(गौतम धर्म सत्र 12-8-13)

"अगर आज मैं बिलकिस के साथ खड़ी नहीं होंगी, तो मैं एक महिला और एक मां होने के नाते फेल हो जाऊंगी"

- खुशबू सुंदर, BJP नेता

बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो की ओर से दायर एक पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें शीर्ष अदालत के 13 मई के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि गैंगरेप और हत्याओं के दोषियों की छूट देने के लिए गुजरात की नीति की बजाए महाराष्ट्र की नीति को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि मामले परीक्षण महाराष्ट्र में हुआ था।

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से बानो द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया।

समीक्षा याचिका में बानो ने कहा कि गुजरात की 1992 की छूट नीति के बजाए महाराष्ट्र की छूट नीति को वर्तमान मामले में लागू किया जाना चाहिए क्योंकि परीक्षण महाराष्ट्र में हुआ था।

शीर्ष अदालत का फैसला दोषियों में से एक, राधेश्याम भगवानदास शाह द्वारा दायर एक याचिका पर आया, जिसमें 1992 की नीति के तहत समय से पहले रिहाई के लिए उनके आवेदन पर विचार करने के लिए गुजरात को निर्देश देने की मांग की गई थी, जो उनकी सजा के समय मौजूद थी।

बानो ने 2002 के गुजरात दंगों में उसके साथ सामूहिक बलात्कार के दोषी 11 लोगों की रिहाई के खिलाफ एक अलग याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि सभी दोषियों की रिहाई न केवल उसके लिए, बल्कि बड़ी हो चुकी उसकी बेटियों व समाज के लिए एक झटके के सामान थी।

बानो ने कहा कि पांच महीने की गर्भवती होने के बावजूद आरोपियों उसके साथ हिंस व क्रूरता की हद को पार करते हुए सामूहिक बलात्कार किया। ऐसे में उन्हें छोड़ना बेहर परेशान करने वाला फैसला है।

स्वाति मालीवाल
अध्यक्ष
दिल्ली महिला आयोग

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो की अर्जी खारिज कर दी। बिलकिस बानो का 21 साल की उम्र में गैंगरेप किया गया, उसके 3 साल के बेटे और परिवार के 6 सदस्यों का कत्ल कर दिया गया, पर गुजरात सरकार ने उसके सभी रेपिस्ट को आजाद कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा, तो कहां जाएंगे

बिलकिस बानो कि दोषियों को मुक्त करने में गुजरात सरकार जिस रिमिशन पॉलिसी का प्रयोग किया है वह एक नया संगत है या कुछ और गुजरात में रिमिशन पॉलिसी से संबंधित दो कानून है जो एक 1992 में था दूसरा संशोधित 2014 का पहले वाले में बलात्कार दोषी का जिक्र नहीं था तथा संशोधित 2014 के कानून में बलात्कार दोषी को शामिल किया गया बिलकिस बानो के दोषियों को सरकार ने 1992 की पार्टी का प्रयोग किया है जबकि अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बलात्कार दोषियों को ना मुक्त करने की एडवाइजरी राज्यों को जारी की थी जिसका भी कुजा सरकार ने अवहेलना की जिस समिति ने दोषियों को मुक्त करने का फैसला लिया क्या वह पीड़िता से बात की जबकि कमेटी ने अच्छे आचरण तथा व्यवहार के आधार पर दोषियों को मुक्त करने की सिफारिश करती है जिस कमेटी में पंचमहल के जिलाधिकारी समेत 10 सदस्य जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्य शामिल थे जिन्होंने सर्वसम्मति से दोषियों को मुक्त करने का फैसला लिया जो गुजरात सरकार के फैसले पर प्रश्नचिन्ह लगाता है कि क्या राज्य ने न्याय के आधारभूत सिद्धांत का पालन किया है या इसके पीछे कुछ और है जिस अच्छे आचरण की बात से मिटने की है 11 दोषियों को जेल में रखा गया था जब यह पैरोल पर बाहर आते थे तो बिल्कुल के गवाहों को धमकाने का कार्य किया जाता था। इतना ही नहीं इस केस की सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार तथा वहां के अधिकारी सीबीआई का सहयोग नहीं कर रहे थे तथा गवाहों को लगातार परेशान किया जाता था जिसका जिक्र सीबीआई प्रमुख ने 2004 में किया था जिस कारण इस पूरे केस को महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया गया इसके परिणाम स्वरूप आरोपियों को दोषी करार दिया गया तथा आजीवन कारावास की सजा दी गई ऐसे में गुजरात सरकार तथा वहां के प्रशासनिक तंत्र से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि बिल किसके साथ न्याय करेगी ऐसे में अंतिम उम्मीद के साथ के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही न्याय की उम्मीद की जा सकती है।

निर्भया कांड के बाद जिस प्रकार बुद्धिजीवी समाज, मीडिया तथा राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया था तथा पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए एक सफल आंदोलन किया था, वैसा बिलकिस बानो के केस के बाद क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमारा समाज आज मुर्दा समाज के रूप में तब्दील हो चुका है। जो कि हिंदू-मुस्लिम जैसे सांप्रदायिक मुद्दों की दृष्टि से दो भाग हो जाता है, वहीं राजनीतिक पार्टी तो सिर्फ वोट बैंक को ध्यान में रखकर अपनी बात रखते हैं। जैसा कि हम ज्वलंत रूप में देख सकते हैं दिल्ली, पंजाब में सत्तारूढ़ नवोदित राजनीतिक पार्टी जो लोकतंत्र में पारदर्शिता तथा सुचिता तथा विधि के समक्ष समता और समानता की बात करती है वह भी अल्पसंख्यक समाज के प्रति मौन धारण किये हुए है। ऐसे में कुछ जागरूक नागरिक तथा संगठनों ने बिलकिस बानो को सुरक्षा दिलाने तथा दोषियों को पुनः कारावास भेजे जाने का अभियान चला रहे हैं जो सराहनीय है जिसमे सामाजिक कार्यकर्ता रूप रेखा वर्मा टीएमसी सांसद मोइआ मित्रा ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। हो सकता है कानूनी प्रक्रिया में बिलकिस के गुनाहगारों को पुनः कारावास हो जाए देश में क़ानून का राज स्थापित हो हम यह सकारात्मक कल्पना या आशा कर सकते हैं, परंतु एक सामाजिक जागरूक तथा चेतना के रूप में हमें विचार करना होगा कि हमारा समाज कहा जा रहा है और किधर जा रहा है जो कभी सामाजिक अधिकारों के लिए आन्दोलनों से नहीं डरता था। ▪

कमलेश यादव
मो.न.- +91 9335806679

कॉलेजियम पर कोलाहल

1980 से लेकर 90 के दशक की शुरुआत में देश की राजनीति की सामाजिक संरचना तेजी से बदल रही थी। खासकर पिछड़े वर्ग की लोक सभा और विधान सभाओं में संख्या बढ़ रही थी और उसी के साथ उच्च जातियों की हिस्सेदारी घट रही है। इस बीच, वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया। इससे सवर्ण तबकों के इलीट घबरा गए। उन्हें लगा कि संसद-विधानसभाओं, मंत्रिमंडलों के बाद अगर नौकरशाही में भी उनका दबदबा टूट गया तो क्या होगा। इसे देखते हुए उन्होंने जजों की नियुक्ति की ऐसी व्यवस्था बनाई जो संसद और सरकार से पूरी तरह आजाद है और जिसमें सवर्ण वर्चस्व बनाए रखने में कोई बाधा नहीं हो, इस तरह वर्चस्ववादी वर्ग ने सत्ता के एक अंग को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया।

▪ **नरेन्द्र प्रताप**

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछले दिनों अहमदाबाद में एक कार्यक्रम और उससे पहले उदयपुर में भावी कानूनी मुद्दों पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए जजों की नियुक्ति के वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम पर कुछ गंभीर सवाल उठाए। बाद में शिलांग में आयोजित एक कार्यक्रम में कानून मंत्री ने अपनी बातों को दोहराया। कानून मंत्री द्वारा बार-बार इस बारे में सवाल उठाए जाने से ये लगता है कि केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था की खामियों को लेकर गंभीर है और इस पर बहस कराना और मुमकिन है कि इस व्यवस्था में सुधार करना या इसे बदलने की सोच रही है।

क्या है कॉलेजियम सिस्टम?

कॉलेजियम सिस्टम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की व्यवस्था है। ये व्यवस्था संविधान से नहीं आई है और न ही इसके लिए संसद में कोई कानून पास किया है। ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों (जजेज केस) से आई है। इसके मुताबिक,

– सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों के ट्रांसफर के फैसले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और चार अन्य सबसे सीनियर जजों का समूह करता है।

– हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दो सबसे सीनियर जजों का समूह करता है।

– हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति की सिफारिश उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और दो सबसे सीनियर जजों का समूह करता है। इन सिफारिशों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दो सबसे सीनियर जज करते हैं।

जजों के समूह यानी कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को मानना सरकार (राष्ट्रपति) के लिए अनिवार्य होता है। सरकार चाहे तो कॉलेजियम से एक बार ये अनुरोध कर सकती है कि वह अपनी सिफारिश पर पुनर्विचार करे, लेकिन कॉलेजियम ने वही सिफारिश फिर से भेज दी, तो सरकार के लिए उसे मंजूर करना जरूरी होता है। यानी कॉलेजियम सिस्टम में सरकार की भूमिका सलाह देने या अपनी असहमति जताने तक सीमित है। इसे मानना या न मानना जजों के समूह के हाथ में है।

संविधान में उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका (सरकार) को प्राथमिकता दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के मुताबिक 'उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के

पश्चात, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा.' संवैधानिक भाषा में इस अनुच्छेद में जो लिखा है, उसका मतलब है कि राष्ट्रपति जजों की नियुक्त के लिए जजों से परामर्श (Consultation) ले सकता है। इसमें राष्ट्रपति की सर्वोच्चता निहित है।

1980 से लेकर 90 के दशक की शुरुआत में देश की राजनीति की सामाजिक संरचना तेजी से बदल रही थी। खासकर पिछड़े वर्ग की लोक सभा और विधान सभाओं में संख्या बढ़ रही थी और उसी के साथ उच्च जातियों की हिस्सेदारी घट रही है। इस बीच, वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया। इससे सवर्ण तबकों के इलीट घबरा गए। उन्हें लगा कि संसद-विधानसभाओं, मंत्रिमंडलों के बाद अगर नौकरशाही में भी उनका दबदबा टूट गया तो क्या होगा। इसे देखते हुए उन्होंने जजों की नियुक्ति की ऐसी व्यवस्था बनाई जो संसद और सरकार से पूरी तरह आजाद है और जिसमें सवर्ण वर्चस्व बनाए रखने में कोई बाधा नहीं हो. इस तरह वर्चस्ववादी वर्ग ने सत्ता के एक अंग को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया।

1993 में कॉलेजियम सिस्टम का आना क्यों महत्वपूर्ण है

सवाल उठता है कि कॉलेजियम सिस्टम को इससे पहले क्यों नहीं लाया गया। दरअसल इसके कारणों को समकालीन राजनीति के समाजशास्त्र से समझा जा सकता है। आजादी के बाद के पहले बीस साल लगभग पूरी तरह कांग्रेस के थे। 1967 में पहली बार उसे तब झटका लगा जब विधानसभा चुनावों के बाद 9 राज्यों में गैर-कांग्रेस दलों की मिली-जुली सरकार बन गई। इन सरकारों में उन जातियों का प्रतिनिधित्व भी था, जिन्हें समेटकर चलने में कांग्रेस विफल साबित हुई थी। इनमें मझौली और अपेक्षाकृत निचली जातियों के संगठन और नेता भी थे।

1977, इस प्रक्रिया का दूसरा अहम पड़ाव था, जब पहली बार केंद्र में कांग्रेस हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी. इस सरकार में पिछड़ी जातियों के कई प्रमुख नेता थे। इसी दौरान दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग यानी मंडल कमीशन का गठन हुआ। हालांकि उसकी रिपोर्ट आने तक जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी। 1977 में ही उत्तर भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में ओबीसी समुदायों के दो नेता- राम नरेश यादव और कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने और दोनों ने अपने अपने राज्यों में पहली बार पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू कर दिया।

ओबीसी का दबदबा राष्ट्रीय राजनीति में पहली बार 1989 में ढंग से दिखा जब कई ओबीसी नेता उभरकर सामने आए और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 1990 का दशक राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक खींचतान के लिए भी जाना जाता है। ये दिलचस्प है कि जिस समय लोकतंत्र का समाज के निचले और मझोले तबकों में विस्तार हो रहा था और वंचित जातियों के लोग राजनीति और राजकाज में हिस्सेदारी लेने की कोशिश कर रहे थे तो अकादमिक संस्थानों में बैठे विद्वान इसे भारतीय लोकतंत्र का संकट बता रहे थे। ये शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि अकादमिक संस्थानों में आम तौर पर वंचित स्वर नहीं हैं या कम हैं।

कॉलेजियम सिस्टम आने के समय के राजनीतिक सामाजिक संदर्भों से ऐसे संकेत मिलते हैं कि संसद, विधानसभाओं, -शेष पेज-9

सुप्रीम कोर्ट का 15 बनाम 85

15-85 की लड़ाई देश में लम्बे समय से चली आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में यह लड़ाई उल्टी दिखाई दे रही है। 15 प्रतिशत आबादी को 85 प्रतिशत और 85 प्रतिशत आबादी को मात्र 15 प्रतिशत भागीदारी है। जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक सभी शामिल है। पिछले पांच वर्षों में उच्च न्यायालयों में नियुक्त न्यायाधीशों में से 15 प्रतिशत से थोड़े अधिक पिछड़े समुदायों से थे।

विभाग ने साथ ही कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों की शुरूआत कॉलेजियम द्वारा की जाती है, इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओं के बीच से उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करके सामाजिक विविधता के मुद्दे को हल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी उसकी बनती है। विभाग ने इसमें कहा कि 30 साल हो गए हैं लेकिन सामाजिक विविधता की आकांक्षा अभी तक हासिल नहीं हुई है।

न्याय विभाग ने साझा किया

- 2018 से 19 दिसंबर 2022 तक, उच्च न्यायालयों में कुल 537 न्यायाधीश नियुक्त किए गए।
- इनमें से 1.3% अनुसूचित जनजाति।
- 2.8% अनुसूचित जाति।
- 11% ओबीसी वर्ग।
- 2.6% अल्पसंख्यक समुदायों से थे।
- 20 नियुक्तियों ऐसी हैं जिनके लिए सामाजिक पृष्ठभूमि पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

न्याय विभाग ने कहा कि सरकार उच्च न्यायालय से मुख्य न्यायधीशों की न्युक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवारों पर उचित विचार किया जाए। विभाग में राष्ट्रीय न्यायिक न्युक्ति आयोग के बारे में भी कहा कि इसमें दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इसके सदस्य के रुप में प्रस्तावित किया। जिनमें एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय या अल्पसंख्यकों या एक महिला से नामित किया गया। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने एनजेएसी को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया।

जेएनयू की पिंक दिवारों पर नफ़रत के लाल छींटे

▪ बसावन इंडिया डेस्क

दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूनिवर्सिटी JNU का एक बार फिर से सुर्ख़ियों में है। इस बार हिंदू-मुस्लिम की जगह विश्वविद्यालय कैंपस में 'ब्राह्मण परिसर छोड़ो', 'रक्तपात होगा', 'ब्राह्मण भारत छोड़ो' और 'ब्राह्मणों और बनिया, हम तुम्हारे पास बदला लेने आ रहे हैं' के नारे लिखे हुए हैं और इतना ही नहीं साथ ही इमारतों की दिवारों की तोड़फोड़ भी की गई। इन नारों में ब्राह्मणों और बनियों को निशाना बनाया गया हैं। जिसको लेकर काफी बवाल देखने को मिल रहा है। फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।

वायरल फोटो में देखा जा सकता है कि दीवारों में लाल रंग से लिखा गया कि, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण और बनिया हम तुम्हारे लिए आ रहे है। बख्शा नहीं जाएगा जैसे धमकी भरे नारे लिखे गए है। इस घटना के बीच एबीवीपी ने लेफ्ट विंग को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं विवाद बढ़ने पर जेएनयू प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए है। जेएनयू की वाइस चांसलर शांतिश्री पंडित ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट मांगी है। जांच के आदेश दे दिए है।

बुद्धिजीवियों की फैक्ट्री जेनयू

आखिर जे एन यू में लिखे गए इन नारों का मतलब क्या है, इन नारों से विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्ख़ियों में आ गया। जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय देश के चुनिन्दा संस्थाओं में से है जहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस हुआ करती है, विचार और चालचलन जो साधारणतः समाज में छुपा लिए जाते हैं, यहां आसानी से अभिव्यक्ति पाते रहे हैं। जब पूरे देश में समलैंगिकता को लेकर हाहाकार मचा हुआ था तो यह उन बिरले परिसरों में था जहां समलैंगिकता की स्वतंत्रता के बारे में लोगों को बहस नहीं करनी पड़ी। जब देश में सिगरेट पीने पर प्रतिबंध लगा तो यहां ही सिगरेट पीने की परम्परा निर्बाध चलती रही। जब देश महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय की बहस में निरर्थक बहस कर रहा था तब महिलाओं को जेएनयू परिसर में स्वच्छंद रहने और काम करने की आज़ादी रही। जब दिल्ली भर में कांग्रेस सरकार की नाक के नीचे सिखों का क़त्ल हो रहा था तब जेएनयू ने ही सिखों को शरण दी। यहाँ से प्रतिवर्ष सैकड़ो की संख्या में लेखक चिन्तक पत्रकार और प्रशासक पैदा होते हैं। यह विश्वविद्यालय अपनी विश्वस्तरीय पढ़ाई और रिसर्च के लिए जाना जाता है। 2016 में जेएनयू भारत की तीसरी बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी जबकि 2017 में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। जेएनयू की स्थापना 1969 में पार्लियामेंट ऐक्ट के तहत की गई थी। इसे भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का खिताब भी मिल चुका है।देश में कई मुद्दों को लेकर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय कई आन्दोलनों की जननी भी रहा है , देश के किसी भी कोने में हो रही किसी भी गतिविधियों के लिए यहाँ के छात्रों को आन्दोलन करते हुए देखा जा सकता है।

डॉ. विक्रम

> **“ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को लेकर हिंदू संगठनों का विरोध हमेशा से रहा है। वामपंथी विचारधारा के चलते जेएनयू पर ब्राह्मणवादी विचार निष्प्रभावी हो जाते है जिसके चलते ब्राहमणवादी हिंदूवादी विचारकों की दाल नहीं गल पाती है यह देश का इकलौता विश्वविद्यालय है, जहाँ ब्रहामंवादियों की दाल नहीं गल पाती है जिसके चलते यह उनकी आँख की किरकिरी बना हुआ है। इस तरह के नारों से किसका भला होगा इसकी जाँच की जानी चाहिए। यह जेएनयू को बदनाम करने की साजिश है। ”**

2014 के बाद विचारधाराओं का टकराव बढ़ा-

जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय में विरोधाभासी विचारों का समर्थन करने वाले दो समूहों के बीच का तनाव हाल के कुछ सालों में बढ़ा है, ख़ासकर 2014 में हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सत्ता में आने के बाद। जेएन यू में बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के कारण विरोधाभासी विचारधाराओं का यह रूप हिंसक भी हो गया था। पिछले साल भी ABVP और वामपंथी संगठन AISA के बीच मारपीट की घटना हुई थी।

विश्वविद्यालय को बदनाम करने या ध्यान भटकाने की साजिश तो नहीं?

आखिर ब्राहमणों भारत छोड़ो जे एन यू छोड़ो लिख कर कौन लोग है जो जेएनयू को ब्राहमणों से आजाद करवाना चाहते हैं, उन्हें ब्राहमणों से क्या खतरे हैं? क्या उनकी आजादी ब्राहमणों से बाधित हो रही है? इन सब मुद्दों ओ समग्रता से सोचना होगा। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र इतने सतही स्तर की राजनीती नहीं कर सकते हैं क्यों की उन्हें पता है की उनके इन नारों से देश में ब्राहमणों और बनियों का कुछ भी नहीं होने वाला है।

बात निकली है तो दूर तलक जाएगी –

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश में अंग्रजो भारत छोडो का नारा बुलंद हुआ, न तो देश वासी अंग्रेजों को स्वीकार कर पाए और न ही अंग्रेज इस देश को स्वीकार किये अंग्रेज विदेशी थे वो चले गए, अंग्रेज के आने और जाने की तारीखें पता थी भारतीय इतिहास की यह बहुत तात्कालिक घटना थी लेकिन ब्राहमण और बनिया भारत में कब आये, यह शोध का विषय है बहुत से विद्वानों ने इस बारे में विस्तार से लिखा है।

जर्मन इतिहासकार मैक्समूलर के अनुसार भारत एवं ईरान के मध्य अवस्थित मध्य एशिया क्षेत्र से निकलकर एक शाखा यूरोप, दूसरी शाखा ईरान एवं तीसरी शाखा भारत में बसी। भारत में जो शाखा आई थी वह शाखा अफगानिस्तान से होते हुये हिन्दूकुश पर्वत को पार करके सप्तसिंधु क्षेत्र आये तथा यहीं पर ये लोग बस गये थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद में वर्णित दीर्घ अहोरात्र, प्रलंबित उषा आदि के आधार पर आर्यों की मूलभूमि को ध्रुवप्रदेश में माना था।

मार्च 2018 में जेनेटिसिस्ट (आनुवांशिकी विज्ञानी) हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डेविड रेक और शोध में पूरी दुनिया के 92 विद्वान सह-लेखक द्वारा 'द जीनोमिक फॉर्मेशन ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया' (The Genomic Formation of South and Central Asia) शीर्षक से एक पेपर ऑनलाइन जारी हुआ था, इसने भारत में आर्यों के प्रवेश के संबंध में दुनिया भर में सनसनी फैला दी थी। इस शोध में कई चौंका देने वाली बातें सामने आई। शोध दिखाता है कि पिछले 10 हज़ार सालों में भारत में दो मौक़ों पर बड़ी संख्या में लोग आए।

पहले तो दक्षिण-पश्चिम ईरान के ज़ैग्रोस प्रांत से बड़े पैमाने पर लोग भारत में आए। इनमें कृषक और संभवतः पशुपालक भी थे। ज़ैग्रोस वही इलाक़ा है, जहां इंसान द्वारा पहली बार बकरी को पालतू बनाने के सबूत मिले हैं।

यह 7,000 से 3,000 ईसा पूर्व के बीच हुआ होगा। इन ज़ैग्रोसयाई पशुपालकों का भारतीय उपमहाद्वीप पर पहले से रह रहे लोगों के साथ मिश्रण हुआ। यहां पर पहले से रहने वाले लोग जिन्हें आप शुरुआती भारतीय या फर्स्ट इंडियंस कह सकते हैं, वे 65000 साल पहले एकसाथ अफ़्रीका से भारत आए थे। इन्हें आउट ऑफ़ अफ़्रीका या OoA माइग्रेंट कहा जाता है, तो इस तरह इन दोनों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता बसाई।

जेएनयू का प्रगतिशील छात्र आंदोलन सामाजिक न्याय की बात करता है। फुले, आम्बेडकर, सावित्री, फातिमा को मानने वाले किसी विशेष समूह को भारत छोड़ने के लिए नहीं कह सकते। इसलिए यहां इस पर ध्यान देने की जरूरत है, और इसकी जांच करने की जरूरत है कि जिन दीवारों पर सामाजिक न्याय के मुद्दे लिखे गए हैं, उन दीवारों पर गुमनामी की आड़ में "भारत छोड़ो" लिखकर कैंपस के माहौल को खराब करने के अपने उद्देश्य को कौन साध रहा है? ▪

पेज-7 का शेष भाग –

सरकारों और नौकरशाही में आ रहे पिछड़ा-दलित उभार से न्यायपालिका को बचाने के लिए कॉलेजियम सिस्टम लाया गया। वंचित जातियों के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आने और उनका प्रभाव बढ़ने के खिलाफ ये सामाजिक रूप से प्रभुत्वशाली वर्ग की प्रतिक्रांति या सुरक्षात्मक रणनीति थी।

1993 में केंद्र की सत्ता कांग्रेस के पास थी और पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। वे कानून मंत्री भी थे। कांग्रेस ने कॉलेजियम सिस्टम लाने की जजों की कोशिश का कभी विरोध नहीं किया। बल्कि बाद में कांग्रेस शासन में कानून मंत्री बने कपिल सिब्बल ने तो 1993 के इस केस में कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष में बहस की थी। इस केस में उन्होंने दलील दी थी कि – 'चीफ जस्टिस जजों के नामों की सिफारिश करें, इसके पहले उन्हें दो या तीन वरिष्ठ जजों से परामर्श करना चाहिए। इस तरह जो राय बनेगी, वह पूरी न्यायिक बिरादरी की राय मानी जाएगी और इसे मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्य होना चाहिए।'

ऐसा माना गया कि इस व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता की रक्षा होगी और सरकार के हस्तक्षेप से न्यायपालिका को बचाया जा सकेगा। चूंकि इससे पहले, खासकर इंदिरा गांधी के शासनकाल में सरकार द्वारा न्यायपालिका को प्रभावित करने के मामले हुए थे, इसलिए जनमत भी इस पक्ष में था कि न्यायपालिका को सरकार के हस्तक्षेप से बचाया जाए। इसलिए उस दौर में, कॉलेजियम सिस्टम का उल्लेखनीय विरोध भी नहीं हुआ।

लेकिन अब कॉलेजियम सिस्टम की बुराइयां सामने आ चुकी हैं। इसके बाद से न्यायपालिका में फैसले देने की रफ्तार बेहद सुस्त पड़ गई है। कई विवाद भी हुए। इस कारण न्यायपालिका की काफी बदनामी हुई है और न्यायपालिका कई बार संकट में भी आई है। ताजा उदाहरण कॉलेजियम के आपसी विवाद के कारण चार जजों की नियुक्ति न हो पाना है।

चीफ जस्टिस यूयू ललित जिन चार जजों को नियुक्त करना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने कॉलेजियम की बैठक बुलाई, पर जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ उस रोज रात 9 बजे तक मुकदमों की सुनवाई करते रहे। इस वजह से बैठक हो ही नहीं पाई।

जस्टिस ललित ने चारों कॉलेजियम जजों से सहमति लेने के लिए पत्र भेजा, जिसका दो जजों ने विरोध कर दिया। इस बीच कानून मंत्रालय ने जस्टिस ललित से कहा कि वे अगले चीफ जस्टिस के लिए नाम भेजें। इसके बाद कॉलेजियम की बैठक करना मुमकिन नहीं था। इसलिए चार जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया। ये बेहद अशोभनीय था और इससे कॉलेजियम के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर चलने वाले दांव-पेच उजागर हो गए। कॉलेजियम सिस्टम के आने के साथ ही न्यायपालिका में सामाजिक विविधता लाने की कोशिशों का अंत हो गया। ▪

प्रमोशन में ओबीसी को आरक्षण दिए जाने की मांग

■ बसावन इंडिया डेस्क

डीएमके सांसद पी विल्सन ने ओबीसी को प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरन रिरिजु को लिखे गए पत्र में कहा कि ओबीसी समुदाय को संवैधानिक रूप से पिछड़ा होने की मान्यता भी है, उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रशासन के रूप में उन्हें पदोन्नति के लिए कभी भी विचार नहीं किया गया था। यहां तक कि वे राज्य भी जो आरक्षण देने में रुचि रखते हैं। ओबीसी के लिए प्रमोशनल पदों पर संवैधानिक न होने का डर सता रहा है। वे आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं लेकिन इसे उपलब्ध कराने के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए जनजाति, संविधान के अनुच्छेद 16(4A) और 16(4B) के तहत अधिकार देता है। राज्य के मामलों में आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए पदोन्नति, किसी भी वर्ग या पदों के वर्गों के लिए परिणामी वरिष्ठता के साथ यदि राज्य की राय में आता है कि वे पर्याप्त रूप से नहीं हैं प्रतिनिधित्व किया। लेकिन ओबीसी के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक जनादेश के ऐसे अभाव के कारण वास्तविक उत्पीड़ित और दलितों को आज तक मुख्य धारा में नहीं लाया गया है। मात्र सेवा में प्रवेश पर्याप्त नहीं है। केवल जब ये समुदाय हैं प्रचारक पदों में माना जाता है, वास्तविक मौलिक समानता हासिल करने में है। यह एक तथ्य है कि ऐतिहासिक अन्याय अभी भी सामने आया है अन्य पिछड़े समुदायों और उच्चतर नौकरियों में उनकी

← Tweet

Rajendra Pal Gautam Retweeted

Dilip Mandal
@Profdilipmandal

भारत की नौकरशाही का सबसे उच्च पद सेक्रेटरी होता है। अभी भारत सरकार में 89 सेक्रेटरी हैं। उनमें एक भी OBC नहीं है। 60% ओबीसी आबादी का उच्च पदों पर न होना चिंताजनक है। DMK सांसद @PWilsonDMK ने सरकार से माँग की है ओबीसी को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए। क्या आपका समर्थन है?

उचित हिस्सेदारी पद अस्वीकृत हैं और आज तक उनका पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है। प्रमोशनल पदों पर राज्यों द्वारा आरक्षण नहीं देने का कारण बकाया है। तथ्य यह भी है कि इसी तरह के संवैधानिक समर्थक प्रावधानों में पाया जाता है। अनुच्छेद 16(4)(ए) या अनुच्छेद 16(4) (बी) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए उपलब्ध है ओबीसी समुदायों के लिए जनजातियां उपलब्ध नहीं हैं।

यदि संविधान का अनुच्छेद 16 अनुच्छेद के समान सक्षम प्रावधान को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है, 16(4ए) और 16(4बी) और पदोन्नति वाले पदों में आरक्षण प्रदान करें परिणामी वरिष्ठता, इन बाधाओं को आसानी से दूर किया जा सकता है। सामाजिक न्याय के लिए ओबीसी उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का परिणाम सही होगा क्योंकि यह प्रशासन के उच्च कार्यालयों में ओबीसी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। वास्तव में एक प्रतिनिधि प्रशासन तभी प्राप्त किया जा सकता है जब वहाँ हो एक तत्काल आत्मनिरीक्षण है और सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

उन्होंने कहाकि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मुद्दे पर विचार करें और लें सुधारात्मक कदम और संशोधन करके एक संवैधानिक संशोधन अधिनियमित करें। अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16(4A) और (4B) के समान प्रावधान सम्मिलित करना और अन्य के लिए परिणामी वरिष्ठता के साथ आरक्षण प्रदान करें। अन्यथा पूर्ण सामाजिक न्याय एक दूर का सपना बनकर रह जाएगा।

ज्ञातव्य है कि एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी थी कि भारत सरकार के 89 सचिवों में से सिर्फ एक सचिव अनुसूचित जाति (एससी) और तीन सचिव अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग से हैं। चौंकाने वाली बात ये है कि इन 89 सचिवों में से एक भी व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से नहीं है। इस सूची में शामिल ज्यादातर सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से हैं।

आरक्षण के मुद्दे केंद्र सरकार हीला हवाली कर रही है,आरक्षण के बावजूद एससी,एसटी

केंद्र सरकार में आरक्षित वर्ग के खाली पड़े पद

वर्ग	ग्रुप ए (प्रतिशत में)	ग्रुप बी (प्रतिशत में)	ग्रुप सी (प्रतिशत में)
अन्य पिछड़ा वर्ग	60.9	74.8	60.3
अनुसूचित जाति	48.5	60.0	45.8
अनुसूचित जनजाति	53.2	60.7	53.3

नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं...

सुनील चाय केन्द्र
एलनगंज, प्रयागराज

पेरियार मय होता भारत...
उत्तर भारत में पेरियार का जलवा

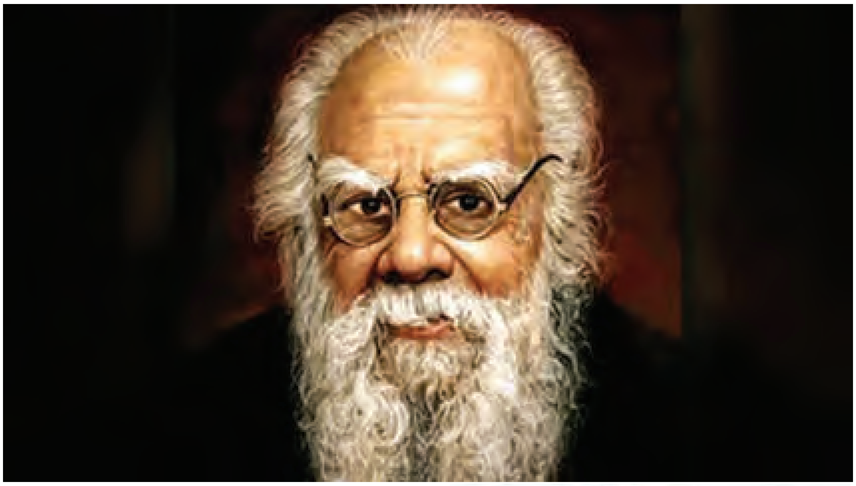

उत्तर भारत में आत्मसम्मान आंदोलन के जनक पेरियार रामास्वामी नायकर का सम्मान करने के लिए बेचैन है जिस प्रकार से पेरियार उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों , चट्टी चौराहों पर दिखे, उनके जन्मदिन मनाये जा रहे हैं उसको देख कर लग रहा है की जल्दी ही सम्पूर्ण भारत पेरियार मय होगा। 17 सितंबर को दक्षिण भारत के महान समाज सुधारक पेरियार रामास्वामी नायकर का आविर्भाव हुआ,जिन्होंने दक्षिण भारत में पोंगापंथियो के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाया और लोगों में रच बस चुके ब्राह्मणवाद से मुक्ति दिलाने का काम किया। जिसका परिणाम है कि दक्षिण भारत की निम्न जातियों में वैज्ञानिक चिंतन का विकास हुआ। लोगों के मध्य तार्किक चिंतन का विकास हुआ। ब्राह्मणवाद की पकड़ ढीली होने का परिणाम ही है कि आज दक्षिण भारत के युवा हर क्षेत्र में आगे हैं।

पेरियार रामासामी नायकर जी ने ईश्वर से ही सवाल पूछ डाले

- क्या तुम कायर हो, जो हमेशा ही छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होते?
- क्या तुम्हें खुशामद पसंद है, जो लोगों से दिन रात पूजा-अर्चना करवाते हो?
- क्या तुम सदैव भूखे रहते हो, जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो ?
- क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि चढ़वाते हो?
- क्या तुम सोने के व्यापारी हो, जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए हुए हो?
- क्या तुम व्यभिचारी हो, जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो?
- क्या तुम कमजोर हो, जो रोजाना होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते?
- क्या तुम मूर्ख हो, जो दुनिया के देशों में गरीबी-भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न, दूध, घी,तेल बिना खाए ही नदी-नालों में बहा देते हो?
- क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते?
- क्या तुम अंधे हो, जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते? क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो, जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो?क्या तुम आतंकवादी हो, जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डरकर रहें?
- क्या तुम गूंगे हो, जो एक शब्द नहीं बोल पाते, लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं?
- क्या तुम भ्रष्टाचारी हो, जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते, जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए धन की पाई-पाई तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देता है?
- क्या तुम मुर्ख हो, जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किये जो तुम्हे खरी-खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं?

प्रयागराज में चौराहे पर पेरियार जयंती

हवाई जहाज बनाने से लेकर चिकित्सा क्षेत्रों में दक्षिण भारत के लोगों का दबदबा है। ब्राह्मणवाद के क्षय का परिणाम ही है कि दक्षिण भारत के लोगों में सेवा भाव अधिक है। वहां की युवतियां आज प्रमुख अस्पतालों में नर्सिंग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही हैं।

धार्मिक आडम्बरों और पोगापंथी की तरफ जो बौधिक तर्क वाद की तरफ बढ़ रहे है, हाल ही में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन को लेकर जिस तरह की हलचल हो रही है उसे देखकर लग रहा है की पेरियार उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहें हैं।

उत्तर भारत में छात्रों के मध्य पनप रहे आक्रोश को भी पेरियार रामास्वामी के आत्मसम्मान आंदोलन से जोड़कर देखा जा सकता है। छात्र शक्ति की अवहेलना प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया हिंदी अंग्रेजी के मध्य किये जा रहे भेद भाव को दक्षिण भारत के आत्मसम्मान आंदोलन से जोड़कर देखा जा सकता है। *पेरियार रामास्वामी नायकर द्वारा मंदिरों में ईश्वर देवी देवताओं का विरोध की कड़ी को उत्तर भारत में बन रहे, राम मंदिर से जोड़कर भी देखा जा सकता है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के व्यापक प्रचार-प्रसार के बावजूद भी युवा अब राम के भरोसे न रहकर रोजगार चाहता है।*

आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में उत्तर भारत के लोगों की सक्रियता बढ़ी है। अम्बेडकर प्रतिमाओं या दलित महापुरुषों के प्रतीकों पर हमले होने की स्थिति में लोग आंदोलित हो कर मुखर विरोध करते है।आज लोग अपने मान सम्मान के लिए किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं हैं।धार्मिक क्षेत्र में भी जकड़न ढीली हुई है, लोग अब तेरहवीं भोज को घृणित मनाने लगे है, पूर्वांचल के कई जिलों में तेरहवीं की जगह अब शोक सभा का आयोजन कर मृत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट किया जा रहा है। लोगों का अब निर्जीव मूर्तियों के प्रति मोह भंग हो रहा है। लोगों में खास कर युवा पीढ़ी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है जिसका सपना पेरियार रामास्वामी ने देखा था।

आज का युवा उन्मुक्त होकर चलाना चाह रहा है। पेरियार रामास्वामी नायकर की शिक्षाओं का परिणाम यह है कि आज का युवा आजीविका के लिए स्वतः ही गतिशील हो गया है।

पेरियार अक्सर अपने भाषण में कहते थे कि आज जब विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर संदेश और अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं तब हम परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर भेज रहे हैं। लगभग 70 साल पहले पेरियार रामास्वामी नायकर ने पाखण्ड मुक्त,तार्किकता वादी और समतावादी समाज का सपना देख था। पेरियार ने दक्षिणी भारत मे अज्ञानता और अंधविश्वास पर अपने विचारों से इतनी चोट की कि युनेस्को जैसी संस्था ने उन्हें नए युग का पैगम्बर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात जैसी उपाधियों से अलंकृत किया।

बीसवीं सदी के मध्य में अज्ञानता अंधविश्वास और बेकार के रीतियों के खिलाफ पेरियार आंदोलन अपने चरम पर था। उनके विचार उत्तर भारत में फैलता उसी समय दक्षिण उत्तर में हिंदी विवाद के नाम पर उनके विचारों को रोकने का काम किया गया। लेकिन विचारों पर किसी का पहरा नहीं है जिसको बांध दिया जाए।

उत्तर भारत के कृषक,मजदूर और पशुपालक जातियों पासी,चमार,धोबी,कोइरी,कुर्मी,अहीरों गड़ेरियो में पेरियार के विचारों बहुत तेजी से जगह बनाई है यही इन समाजों के उत्थान की कुंजी साबित होगा। पाखंडी धर्मो की पकड़ कमजोर होगी पतन और लोगों में वैज्ञानिक विचारों और मूल्यों का संचार होगा,जिसमे हिन्दू धर्म भी शामिल है। जैसा की प्रख्यात समाजशास्त्री और विचारक काँचा इलैया ने माना है कि भविष्य में हिन्दू धर्म रहेगा या खत्म हो जाएगा,इसमे ऐतिहासिक शूद्रों में से चरवाहा समुदाय और पशुपालक समुदाय खास कर अहीरों यानी यादवों की भूमिका निर्णायक होगी। जैसे ही भारत भर के अहीर शिक्षित हुए और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अपनी संस्कृतिक महानता देख पाने में सक्षम हुए, ब्राह्मणवाद का वही हश्र होगा जो ताश के पत्तों के घर का होता है।

आज की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि पेरियार का मिशन चल नहीं अब दौड़ पड़ा है। धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों में जकड़ते जा रहे आज के समय में समाज को जिम्मेदार बनाने के लिए उत्तर भारत के लोगों को पेरियार को समझने की जरूरत है।आरक्षण के लिए आजादी से पूर्व ही कांग्रेस से दो-दो हाथ करने वाले पशुपालक (शेफर्ड यानी गड़ेरिया) जमात के महानतम समाज सुधारक

लखनऊ में पेरियार जयंती समारोह

Dilip Mandal @Profdilipmandal
उत्तर भारत में पेरियार का बढ़ता जलवा!

आज पेरियार जयंती पर उत्तर भारत में सैकड़ों आयोजन हुए। ऐसा ही एक आयोजन लखनऊ में हुआ, जिसमें डीएमके @arivalayam सांसद और NEET में ओबीसी आरक्षण की लड़ाई कोर्ट में जीतने वाले @PWilsonDMK भी आए। #HBDPeriyar144

Translate Tweet

9:23 pm · 17 Sept 22 · Twitter for iPhone

पेरियार रामास्वामी नायकर जी की प्रासंगिकता आज और ज्यादा है।

पेरियार ने जिस तार्किक ढंग से धार्मिक पाखण्ड को खण्ड-खण्ड किया अकाट्य व ग्राह्य रहा।उनकी लिखित पतली सी "सच्ची रामायण" किताब बाल्मीकि व तुलसी दास जी के "रामायण" व "रामचरित मानस" पर भारी है।इसका हिंदी में अनुवाद ललई सिंह यादव ने किया , जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। ललई सिंह यादव को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के बाद जीत मिली। जस्टिस श्री ए के कीर्ति ने 19 जनवरी 1971 को बहुमत से निर्णय दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार की पुस्तक 'सच्ची रामायण' जप्ती की आज्ञा निरस्त की जाती है। जप्त शुदा पुस्तकें सच्ची रामायण याची को वापस की जाएँ और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से तीन सौ रुपये याची को खर्चे के लिए दिलाये जाएँ। सच्ची रामायण अभी भी उत्तर भारत के लोगों के लिए किसी किताब की दूकान पर नहीं मिल सकती।लेकिन सच्ची रामायण को जन -जन तक पहुँचाने के लिए और अंधविश्वास, कूप मंडूकता व मूढ़ता जैसी बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए फूले-अंबेडकरी मिशन के लोग लगे हुए है। जिन पुजारियों, पंडा,मौलवियों, पादरियों और पूजीपतियों को अंधविश्वास से फायदा है वे इसे खत्म नहीं होना देना चाहते हैं। लेकिन आज स्थितियां बदल रही है, पेरियार के विचारों की प्रासंगिकता बढ़ रही है। लोगो को इन विचारों में मुक्ति की कुंजी दिखाई दे रही है।पाखण्डवाद के सहारे जीविकोपार्जन करने वालो के लिए

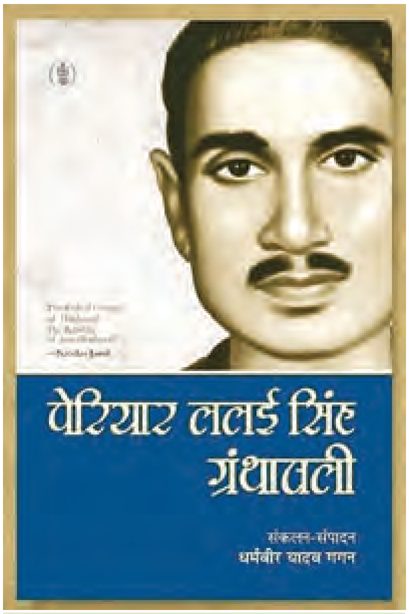

राधेश्याम गौतम
सामाजिक कार्यकता

पेरियार रामा स्वामी नायकर के जन्मदिवस पर ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों पर पेरियार छाए रहे। जब कि पेरियार के लोगों की पहुँच अभी तक सोशल मीडिया पर बहुत कम है और तमाम बाधाओं के बावजूद पेरियार उत्तर भारत मे पहुंच ही गए। इलाहाबाद, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया जिलो के छोटी छोटी जगहों और गाँवों में पेरियार जयंती धूमधाम से मनाई गई,अब इसे रोका भी नहीं जा सकता।

पेरियार साहब का नाम बिजली के करेंट जैसा है जिसका उच्चारण मात्र उन्हें बेसुध कर देता है लेकिन अफसोस यह है कि वह लोग जिनके लिए पेरियार साहब ने पूरे जीवन संघर्ष किया वे ही पाखण्डवाद में आकंठ डूबे हुये हैं। महिलाओं को शादी और बच्चों तक सीमित रखने वाले पाखंडी धर्म भीरुओ के ऊपर पेरियार के विचार करारी चोट है कि आज महिलायें पुरुषों से कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है।

आधुनिक भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि असुरबलि महानायक पेरिया ई.वी. रामास्वामी ने इस मिथकीय भूमि की मानसिकता को बुद्धि और रेसनल्टी से ध्वस्त करने की कोशिश की। उसे अपनी बौद्धिक मेधा से साफ़ करने की कोशिश की। भारतभूमि का भौतिक दृष्टि से निर्माण करने की कोशिश की। इसी कारण आधुनिक भारत के वास्तविक निर्माता सामाजिक परिवर्तन के महानायक पेरियार ई.वी. रामास्वामी को माना जाता है।उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले ललई सिंह यादव ने उत्तर भारत में रामास्वामी पेरियार के साहित्य और चिंतन को हिंदी में लाने का विस्तृत खोजपरक कार्य किया। ललई सिंह यादव पर धर्मवीर यादव गगन द्वारा सम्पादित पुस्तक पेरियार ललाई सिंह ग्रंथावली का प्रकाशन हुआ, जिसका प्रथम एडिशन देखते ही देखते बाजार से गायब हो गया।

इस दौर में गाँव - गाँव में लोगों ने विशेषकर युवा वर्ग और बच्चों ने पाखण्डवाद को खंड खंड करते हुए पेरियार का जन्मदिन मनाया, आने वाले वर्षों में पेरियार लोगों की दिनचर्या में शामिल होंगें, और आडम्बर को लेकर युवा पीढ़ी सवाल जरूर खड़ा करेगी।तब वैज्ञानिक भारत का, तार्किक भारत निर्माण होगा। आज ज्यादातर वैज्ञानिक संस्थान दक्षिण भारत में हैं। आने वाले पेरियार मय भारत में ग़ाज़ीपुर जौनपुर लखीमपुर , आज़मगढ़ छपरा सिवान बाँदा और बलिया से टेक्नोक्रेट , सर्जन , जेनेटिक्स , बायोटेक विशेषज्ञ से लेकर इथिक्स में महारत वाले लोग ,फ़िल्मकार, कलाकार, जानकार चिंतक और लेखक भी निकलेंगें। ▪

नरेन्द्र प्रताप
मो.न.- 9453171770

बुद्धं शरणं गच्छामि

दिल्ली के करोल बाग स्थित अंबेडकर भवन में अशोक विजयदशमी के दिन देश के कोने-कोने से और दिल्ली व आस-पास के इलाकों से आकर लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में लगभग 10 हजार लोगों ने बौद्ध दीक्षा ली।

कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजिंदर पाल गौतम द्वारा किया गया। इसमें डॉ. बी आर आंबेडकर के पौत्र और बुद्धिस्ट सोसयिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजरत्न आंबेडकर के साथ कई बौद्ध भिक्षुओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मौजूद 10 हजार लोगों को राजरत्न अंबेडकर ने दीक्षा देते हुए 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई।

चलो बुद्ध की ओर

कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि

हम अपने पूर्वजों को फिर से अपना रहे हैं। बाबा साहब ने बौद्ध के रास्ते पर चलकर विश्व गुरु बनने का सपना देखा था। उसे पूरा करने जा रहे हैं।

“जाति व्यवस्था के कारण हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, जबकि हमारी संख्या सबसे अधिक है।”

“अब हमें सिर्फ नौकरियों में ही आरक्षण नहीं चाहिए। बल्कि जमीनों पर भी हिस्सा चाहिए।”

“सरकार ने वैसे ही सरकारी नौकरियां धीरे-धीरे खत्म कर दी हैं। अगर कोई वैकेंसी आ भी जाती है तो उनमें समाज के लोगों को लिया ही नहीं जाता है। उसमें आरक्षित सीटें नहीं होती है। अब जरूरी है कि हमें बराबरी का हक मिले। सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया जाए”।

← Tweet

Rajendra Pal Gautam
@AdvRajendraPal

चलो बुद्ध की ओर मिशन जय भीम बुलाता है।

आज "मिशन जय भीम" के तत्वाधान में अशोका विजयदशमी पर डॉ०अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर 10,000 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में घर वापसी कर जाति विहीन व छुआछूत मुक्त भारत बनाने की शपथ ली।

क्या हैं प्रसिद्ध 22 प्रतिज्ञाएँ

1. मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूँगा और न ही मैं उनकी पूजा करूँगा।
2. मैं राम और कृष्ण, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, में कोई आस्था नहीं रखूँगा और न ही मैं उनकी पूजा करूँगा।
3. मैं गौरी, गणपति और हिन्दुओं के अन्य देवी-देवताओं में आस्था नहीं रखूँगा और न ही मैं उनकी पूजा करूँगा।
4. मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ।
5. मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार-प्रसार मानता हूँ।
6. मैं श्रद्धा (श्राद्ध) में भाग नहीं लूँगा और न ही पिंड-दान दूँगा।
7. मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूँगा।
8. मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूँगा।
9. मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ।
10. मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूँगा।
11. मैं बुद्ध के आष्टांगिक मार्ग का अनुशरण करूँगा।
12. मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूँगा।
13. मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूँगा तथा उनकी रक्षा करूँगा।
14. मैं चोरी नहीं करूँगा।
15. मैं झूठ नहीं बोलूँगा।
16. मैं कामुक पापों को नहीं करूँगा।
17. मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा।
18. मैं महान आष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूँगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूँगा।
19. मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है क्योंकि यह असमानता पर आधारित है, और स्व-धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ।
20. मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ की बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है।
21. मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ (इस धर्म परिवर्तन के द्वारा)।
22. मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि मैं इसके (धर्म परिवर्तन के) बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूँगा।

विनोद कुमार
अधि. इलाहबाद उच्च न्यायलय

भारत में आज सिर्फ बौद्ध धर्म ही एक मात्र ऐसा धर्म है जो भारत को विश्व गुरु बना सकता है। समता, बंधुत्व और तर्कवाद की अवधारणा पर आधारित बौद्ध धर्म में दकियानूसी परंपराएं नहीं है। और न ही जाति के आधार पर भेद-भाव होता है। इसीलिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अपने अनुयाइयों को बौद्ध धर्म अपनाने को प्रेरित किया।

हम बौद्धमय भारत बनाएंगे। जहां सब बराबर हों। वह कहते हैं, आज तेजी से लोग अपनी पूर्वजों की विरासत को स्वीकार कर रहे हैं। जिसका नतीजा यह है कि लोग बौद्ध की तरफ मुड़ रहे हैं।

इस साल हमने सिर्फ 10 हजार लोगों की बौद्ध दीक्षा के बारे में सोचा था, लेकिन आज पूरे देश में एक लाख लोगों ने बौद्ध दीक्षा ली है। जिसमें सिर्फ दिल्ली में 10 हजार लोगों ने घर वापसी की है। तमिलनाडू से लगभग 150 डॉक्टर ने 25 लाख की स्पाइस जेट की एक पूरी विमान को बौद्धमय भारत बनाने का पोस्ट लगाकर चेन्नई से नागपुर लेकर आएं हैं। जहां बाबा साहब ने दीक्षा ली थी।

"बौद्ध की शिक्षा का प्रसार अब रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं खुद साल 2025 में सामनेर बनकर पूरे देश में बौद्ध की शिक्षा का प्रचार करूंगा"।

अपने भाषण में जातिव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए राजिंदर पाल गौतम ने राजस्थान के जालौर और बाड़मेर की घटना का जिक्र किया। "यह कैसा धर्म है, जहां किसी का अच्छा कपड़ा पहनना और मूछे रखना उसकी मौत का कारण बन जाएगा। ऐसे धर्म को हमें छोड़ देना चाहिए जो हमारी जान की रक्षा नहीं कर सकता है।"

22 प्रतिज्ञाएं क्यों?

डा बी.आर. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म में "वापस लौटने" के अवसर पर,15 अक्टूबर 1956 को अपने अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाएँ निर्धारित कीं.उन्होंने इन शपथों को निर्धारित किया ताकि हिंदू धर्म के बंधनों को पूरी तरह पृथक किया जा सके.ये 22 प्रतिज्ञाएँ हिंदू मान्यताओं और पद्धतियों की जड़ों पर गहरा आघात करती हैं।

किन-किन लोगों ने दी प्रतिज्ञाएं-

घासीदास की सात प्रतिज्ञाएं

1 सतनाम को मानो, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। सत म धरती सत म अकास।
2 सभी जीव समान हैं। जीव हत्या पाप है। पशु बलि अंध विश्वास है।
3 माँसाहारी मत बनो, नशा मत करो।
4 मूर्ति पूजा मत करो।
5 दोपहर में हल मत जोतो।
6 पर नारी को माता जानो, आचरण की शुद्धता पर जोर दो।
7 चोरी करना पाप है। हिंसा करना पाप है। सादा जीवन उच्च विचार रखो।

बुध के अष्टांगिक मार्ग

बौद्ध धर्म के अनुसार, चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांग मार्ग है - दुःख निरोध पाने का रास्ता। गौतम बुद्ध कहते थे कि चार आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए :

1. सम्यक दृष्टि : चार आर्य सत्य में विश्वास करना
2. सम्यक संकल्प : मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना
3. सम्यक वाक : हानिकारक बातें और झूठ न बोलना
4. सम्यक कर्म : हानिकारक कर्म न करना
5. सम्यक जीविका : कोई भी स्पष्टतः या अस्पष्टतः हानिकारक व्यापार न करना
6. सम्यक व्यायाम : अपने आप सुधरने की कोशिश करना
7. सम्यक स्मृति : स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना
8. सम्यक समाधि : निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना

संवैधानिक प्रावधान

संविधान व्यक्ति को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को त्यागने या अपनाने की स्वतंत्रता देता है। इस नाते जिन लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, यह उनकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है।

कहाँ कहाँ बौध सम्मलेन आयोजित किये गए-

दिल्ली में 5 अक्टूबर को बौद्ध दीक्षा कार्यक्रम में विवादित शपथ ग्रहण को लेकर बवाल थमा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के स्मृति उपवन में एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमे बड़ी संख्या में बौध धर्म की शपथ और दीक्षा ली कार्यक्रम में 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया गया। ▪

परिभाषा
मो.न.- +91 8826063330

2022 की 22 घटनाएं

अच्छी-बुरी यादों के साथ वर्ष 2022 खत्म हो गया। अब नया साल 2023 नई आशाओं को लिए शुरू हो रहा है। बसावन इंडिया ने साल 2022 की 22 घटनाएँ जो विशेष रही को संकलित किया है। जिसमें अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं आंचलिक खबरे, स्टोरी एवं सख्सियत को शामिल किया गया है।

हेमंत सोरेन सरकार ने इतिहास रचा।

14 सितंबर, 2022 को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इतिहास रचा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में दो बड़े फैसले लिये गये। इनमें एक गैर सवर्णों के लिए राज्याधीन नौकरियों व उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाकर 67 फीसदी किया जाना है। वर्तमान में झारखंड में पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 14 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (एससी) को 10 प्रतिशत, और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को 26 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा आर्थिक आधार पर कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। झारखंड में वर्तमान में कुल 60 प्रतिशत आरक्षण है। राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद अब वहां ओबीसी को 27 फीसदी, एससी को 12 फीसदी और एसटी को 28 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इस प्रकार गैर-सवर्णों के लिए कुल आरक्षण अब 67 फीसदी हो जाएगा।

महज एक नस के सहारे लटकी गर्दन को जोड़कर युवक को नया जीवन दिया।

किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय (केजीएमयू KGMU) लखनऊ के थोरेसिक विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. शैलेंद्र यादव की टीम ने महज एक नस के सहारे लटकी गर्दन को जोड़कर युवक को नया जीवन दिया। सिर्फ एक नस के सहारे उसका सिर धड़ से जुड़ा रह गया। सड़क के किनारे लगे कटीले तार से रगड़ खा कर सांस और खाने की नली भी कट गई थीं। केजीएमयू में थोरेसिक विभाग के अध्यक्ष डॉ. शैलेंद्र यादव की निगरानी में मरीज को भर्ती किया गया। डॉ. शैलेंद्र यादव ने युवक को बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि सबसे पहले खून और फिर खाने व सांस की नली को जोड़ा गया।करीब पांच घंटे तक चली जटिल सर्जरी के बाद युवक की जान बचने में सफलता मिली।

क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली साम्राज्ञी थीं।

70 साल के शासन के बाद यूनाइटेड किंगडम और 14 अन्य राष्ट्रमंडल क्षेत्रों की रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 8 सितंबर को दुनिया को अलविदा कहा। क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली साम्राज्ञी थीं। ब्रिटेन की महारानी के पद पर उनकी ताजपोशी साल 1952 में हुई थी। वो 70 साल तक इस पद पर बनी रहीं। सिर्फ 25 साल की उम्र में ब्रिटेन की राजगद्दी संभालने वाली एलिजाबेथ ने तीन बार भारत का दौरा किया था। 1961, 1983 और 1997 में वो भारत आई थीं। उनके निधन पर भारत सरकार ने 11 सितंबर को राष्ट्रीय शोक का एलान किया।

मोरबी ब्रिज हादसा 141 लोगों की मृत्यु

30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी नामक शहर के मच्छु नदी में बने पूल टूटने पर 141 लोगों की मृत्यु हो गई। अधिक पैसे वसूली के चक्कर में इसकी क्षमता से अधिक लोगों को इस पर जाने की अनुमति दे दी गई थी। इस पुल का स्वामित्व मोरबी नगर पालिका के पास है, जिसने इस पुल के रख रखाव और मरम्मत हेतु कुछ महीने पहले एक निजी ट्रस्ट ओरेवा (अजंता मैनुफेक्चुरिंग प्राइवेट लिमिटेड) को काम दिया था। ओरेवा को इस पुल के रख रखाव और मरम्मत के लिए 15 वर्षों का अनुबंध किया गया था।

रुस ने यूक्रेन पर किया आक्रमण

24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के साथ चल रहे तनाव के बीच यूक्रेन पर आक्रमण किया। वहीं, इसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप के सबसे बड़े शरणार्थी संकट को जन्म दिया है। रूस यूक्रेन के NATO का सदस्य बनने के खिलाफ है। जब यूक्रेन नहीं माना और NATO की सदस्यता लेने पर अड़ा रहा तो उसे सबक सिखाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। जंग के चलते यूक्रेन से लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। पड़ोसी देशों में बड़ी संख्या में यूक्रेन के नागरिकों को शरण ली। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) के कार्यालय ने 18 दिसंबर 2022 तक यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दौरान कुल 6,826 नागरिकों की मौत

की पुष्टि की उनमें से 428 बच्चे थे। इसके अलावा, 10,769 लोग घायल हुए।

स्टालिन को के. वीरामणि सोशल जस्टिस अवार्ड

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को के. वीरामणि सोशल जस्टिस अवार्ड-2022 से सम्मनित किया जाएगा। इस आशय की घोषणा चेन्नई में गत 2 दिसंबर, 2022 को द्रविड़ कषगम के प्रसिद्ध नेता रहे के. वीरामणि के 89वें जन्मदिन के मौके पेरियार इंटरनेशनल, अमेरिका द्वारा आयोजित एक कर्यक्रम के दौरान की गई। इस मौके पर स्टालिन स्वयं भी मौजूद थे। अपने संबोधन में उन्होंने सम्मान के लिए संस्था के सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया तथा के. वीरामणि के साथ संस्मरणों को साझा किया। बताते चलें कि के. वीरामणि सोशल जस्टिस अवार्ड सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया जाता है

नासा को मिली एस्टरॉयड का रास्ता बदलने में कामयाबी

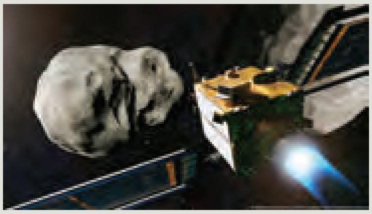

मानव इतिहास में 28 सितंबर के दिन को हमेशा याद रखा जाएगा. इस दिन नासा ने धरती के पास से गुज़र रहे एस्टरॉयड (क्षुद्र ग्रह) से स्पेसक्राफ्ट की टक्कर कराकर उसका रास्ता बदलने में कामयाबी हासिल की। ये टक्कर ये जानने के लिए कराई गई थी कि अंतरिक्ष से धरती की तरफ आने वाली बड़ी चट्टानों और क्षुद्र ग्रहों को धरती की तरफ आने से रोका जा सकता है या नहीं,इस टेस्ट के ज़रिए ये साबित हो गया कि ऐसा किया जा सकता है।

इंद्र कुमार मेघवाल की मौत

राजस्थान में एक नौ साल के मासूम दलित बच्चे इंद्र कुमार मेघवाल की मौत हो गई। मामला सूबे के जलोर जिले के सायला क्षेत्र के सुराना गांव की है। मृतक मासूम स्थानीय सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में तीसरी कक्षा का छात्र था। इंद्र कुमार मेघवाल ने प्रधानाध्यापक छैल सिंह के लिए राखी पानी की मटकी से पानी पी लिया था जिसको लेकर स्कूल के प्रधानाध्यापक छैल सिंह ने मासूम को इतनी जोर से मारा कि उसके दिमाग की नस फट गई और 23 दिनों तक मौत से संघर्ष करने के बाद उसकी मौत गत 13 अगस्त, 2022 को अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन

महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन-साल 2022 में महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन देश की सियासी इतिहास की एक दिलचस्प घटना के तौर पर याद किया जाएगा। शिवसेना में एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के चलते उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा। उद्धव ठाकरे के साथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के साथ शिवसेना के सिंबल और पार्टी से उद्धव को हाथ धोना पड़ा। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से निकलकर नए गुट का गठन कर भाजपा के साथ सरकार बना ली।

मूसेवाला की पंजाब के मानसा में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी

साल 29 मई को सिंगर, एक्टर, रैपर और पॉलिटिशियन रहे सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के वक्त मूसेवाला खुद अपनी थार जीप चला रहे थे। तभी सामने से काले रंग की एक गाड़ी आई, जिसमें मौजूद लोग थार पर लगातार गोलियां चलाने लगे। सिद्धू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। कांग्रेस सरकार में मूसेवाला की सुरक्षा तगड़ी थी। उनकी सिक्योरिटी में पंजाब पुलिस के 10 जवान हर वक्त मौजूद रहते थे। लेकिन पंजाब में भगवंत मान की सरकार बनने के बाद उनकी सुरक्षा घटा दी गई। उनके पास 10 की जगह केवल 2 सिक्योरिटी गार्ड ही छोड़े गए थे।

ट्विटर के नये मालिक : एलन मस्क

इस साल की सबसे चर्चित डील एलन मस्क और माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर की रही। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीदा और उसके बाद कंपनी में कई तरह के बदलाव किए। इसके लिए एलन मस्क और ट्विटर कंपनी के बीच काफी बहसबाजी भी हुई। कंपनी यहां तक कि एलन मस्क को कोर्ट ले गई लेकिन आखिर में एलन मस्क (Elon Musk) ने ट्विटर को खरीद लिया और पराग अग्रवार को बाहर का रास्ता दिखाया।

बिहार में बदलाव

साल 2022 में बिहार की राजनीति में भी बदलाव वाला साल बनकर आया। नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर एक बार भी अपने पुराने दोस्त लालू प्रसाद यादव के साथ दोस्ती गांठ कर 2024 में मोदी के चेहरे को चुनौती देने की तैयारी करते हुए दिखाई दिए। नीतीश से सियासी दांव से भाजपा चारों खाने ति हो गई। नितीश के इस कदम से 2024 में बिहार में भाजपा के लिए कठिनाई होगी।

आठ राज्यों में चुनाव

राजनीति के क्षेत्र में साल 2022 बहुत महत्वपूर्ण रहा। इस साल पांच राज्यों में चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के चुनाव परिणाम देश की राजनीति के लिए एक नई दिशा बने। यूपी और उत्तराखंड में भाजपा की वापसी हुई। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने विपक्ष का सफाया कर दिया। गोवा और मणिपुर में भी भाजपा सत्ता में आई। साल के अंत में हिमाचल प्रदेश, गुजरात विधानसभा में चुनाव परिणाम आए। गुजरात में भाजपा दोबारा सत्ता में आई और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी।

आज़म खान को जमानत

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को 27 महीने बाद जेल से रिहाई मिल गई। साल 2017 में यूपी में योगी सरकार के आने के बाद राजनीतीवश आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक कुल 89 मुकदमे दर्ज किए गए। 27 महीने जेल में रहने के बाद आजम खान को सभी मामलों में जमानत मिल गई है वैसे ये पहला मौका नहीं है जब आजम खान महीनों जेल में बिताकर आ रहे हों, आपातकाल के दौरान भी वे जेल में रहे थे। इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में देश में लगाई गई इमरजेंसी का विरोध करने के चलते आजम खान को जेल जाना पड़ा था। तब वो 19 महीने सलाखों के पीछे रहने के बाद बाहर आए थे।

भारत जोड़ो यात्रा

राहुल गांधी ने सात सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत की थी, अब तक दस से अधिक राज्यों से गुजर चुकी इस यात्रा से सत्ताधारी भाजपा के लिए समस्या खड़ी हो रही है। राहुल गांधी की जुझारु प्रवृत्ति और जनता में बनी सकारात्मक छवि से 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से महात्तवपूर्ण है। क़रीब 3750 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद कश्मीर पहुंचेंगे जहां यात्रा ख़त्म यात्रा के दौरान कई जाने-माने लोग इसमें शामिल हुए

बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे निकाय चुनाव

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से जारी ड्राफ्ट नोटिफ़िकेशन को रद्द कर दिया है और ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के लिए कहा है। नोटिफ़िकेशन में उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फार्मूला लागू किया था, उस पर कोर्ट सहमत नहीं हुआ|इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर पांच दिसंबर को जो अधिसूचना जारी की थी उसे भी खारिज़ कर दिया है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। अन्य प्रदेशों में भी आरक्षण को समाप्त करने के लिए भाजपा ने इसी तरह के दाव-पेंच चले है।

श्रीलंका में सामाजिक-आर्थिक संकट

श्रीलंका इस समय अपने इतिहास के बदतरीन सामाजिक-आर्थिक संकटों से गुज़र रहा है, देश की आर्थिक व्य वस्थास पूरी तरह से चौपट हो गई है। जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी कर पाने में सरकार असफल हो गई है। पेट्रोल-डीजल से लेकर दूध और दूसरी खाद्य सामग्रियां इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। कभी पर्यटन के लिए दुनिया में मशहूर यह आइलैंड आर्थिक तौर पर तबाह हो चुका है। हालात इतने बुरे हैं कि आजादी के बाद एक बार फिर श्रीलंका गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया है।

राजस्थान की पहली बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल

राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल ने थाईलैंड में हुई वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भारत का नाम रोशन कर दिया। विदेशी धरती पर बॉडी बिल्डिंग में प्रिया सिंह ने अपना लोहा मनवाया और गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया।

मंदुरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण विरोध

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मंदुरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का किसान जबर्दस्त विरोध कर रहे हैं। खिरियाबाग में चल रहे ग्रामीण किसान लगभग 80 दिनों से धरने पर हैं। किसानों का यह आंदोलन चर्चा में तब आ गया है। जब पुलिस ने आन्दोलन का नेत्रित्व कर रहे राजीव यादव को धरना स्थल से उठा लिया|आंदोलन को धार देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर और किसान नेता राकेश टिकैत पहुँच कर आन्दोलन को अपना समर्थन दिया। सामाजिक कार्यकर्त्ता संदीप पांडेय धरना स्थल पर ही डटे हुए हैं |

'हमारे पास ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है, जो उसके आसपास भी हो'

सूर्य कुमार यादव जिन्हें लोग स्काई नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के मूल निवासी हैं। टी 20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव ने धमाल मचाया था। वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में तीसरे नंबर पर काबिज रहे। सूर्या इस समय आईसीसी टी 20 की बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर काबिज हैं। आज दुनियाभर में दिग्गजों ने भी सूर्या का लोहा माना है। सूर्यकुमार ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी 20 मैच में शतक जमाया है। सूर्या ने 51 बॉल पर नाबाद 111 रन बनाए थे। इस पारी लेकर मैक्सवेल ने कहा, सूर्या पूरी तरह से अलग ही ग्रह पर बल्लेबाजी कर रहा है। बाकी सभी खिलाड़ियों के स्कोर देखो और इस लड़के को 50 बॉल पर 111 रन बनाते देखो, हमारे पास ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है, जो उसके आसपास भी हो'।

सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के जसोवर गांव की बेटी सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी। सानिया मिर्जा के पिता एक टीवी मेकेनिक हैं।हिंदी मीडियम से यूपी बोर्ड से इंटर की सानिया मिर्जा ने अपनी सम्पूर्ण ऊर्जा राष्ट्रसेवा हेतु कुछ अलग करने की तरफ लगाई और तैयारी कर उन्होने वह मुकाम हासिल कर लिया जो अब तक भारत की किसी मुस्लिम बेटी ने हासिल नहीं किया है। गांव से निकलकर तथा यूपी बोर्ड व हिंदी मीडियम का होकर डिफेंस का कम्पटीशन फेस करना,लड़की होकर फाइटर प्लेन उड़ाने की बात सोचना,मुस्लिम बालिका का ऐसे जोखिम भरे कार्य को अपनाना आदि अनेक सवालों का एक उत्तर बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ राष्ट्रभक्ति को किसी धर्म की सीमा में बांधने वालो के लिए सानिया मिर्जा का चयन एक तमाचा भी हैं

ट्रेन है या टिन का डिब्बा

सवा महीने में वंदे भारत से हुए 4 हादसे, पहले गाय-भैंस अब महिला टकराई। वंदे भारत ट्रेन लगातार हादसों का शिकार हो रही है। मंगलवार को इस ट्रेन से चौथा हादसा हुआ। आणंद में हुए इस हादसे में रेलवे ट्रैक पार कर रही एक महिला की मौत हो गई। इससे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस गाय और भैंसों के झुंड से टकरा गई थी। देश में इस समय सिर्फ चार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। इसके बावजूद पिछले सवा महीने में वंदे भारत ट्रेनों से चार हादसे

हो चुके हैं। पिछली दुर्घटनाओं (Vande Bharat Train Accident) में मवेशी इन दुर्घटनाओं का शिकार हुए। लेकिन आज के हादसे में तो एक महिला की जान चली गई। गुजरात के आणंद में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। इससे पहले यह अहमदाबाद, आणंद और वलसाड में मवेशियों से टकराई थी। इन दुर्घटनाओं में वंदे भारत ट्रेन का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इन दुर्घटनाओं के चलते सोशल मीडिया पर वंदे भारत ट्रेन की खूब थू-थू भी हुई। लोगों ने कहा कि यह ट्रेन है या टिन का डिब्बा! कई सोशल मीडिया यूजर्स ने वंदे भारत को लेकर खूब मीम बनाए। ▪

__बसावन इंडिया राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका__ का संचालन सहकारिता के आधार पर किया जा रहा है। पत्रिका को आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। संपादक मंडल की हर संभव कोशिश है कि खबरों को निष्पक्ष और तथ्यपूर्ण तरीके से पाठकों तक पहुंचाया जाए। यदि फिर भी कहीं कोई कमी रह जाती है तो हम अपने सम्मानित पाठकों से आशा करते हैं कि वे हमारा ध्यानकर्षण करेंगे। साथ ही साथ हम आपके लेख और विचारों का basavanindi@gmail.com पर स्वागत करते है। बसावन इंडिया की कोशिश होगी कि वह आपके लेख और विचार संपादन के बाद प्रकाशित करें। यदि जगह के अभाव और मुद्दों के प्राथमिकता में आपके विचार और लेख छूट जाते हैं तो उसे अगले अंक में लेनें की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा।

सदियों में पैदा होता है तुझसा कोई शख्स मुलायम

▪ बसावन इंडिया डेस्क

हाल के दिनों में भारत और पड़ोसी देश चीन के बीच जिस तरह के हालात बने। उसको देखते हुए। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह, जिनका अक्टूबर 2022 में निधन हो गया , की याद आना स्वाभाविक है, सेना ने उन्हें बेस्ट रक्षामंत्री माना था। मुलायम सिंह ने चीन से सतर्क रहने की जरूरत बताई थी।

मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में एक किसान परिवार हुआ था। वे छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रहे|उन्होंने राजनीति शास्त्र में डिग्री हासिल करने के बाद एक इंटर कॉलेज में कुछ समय के लिए पढ़ाया।

वह पहली बार 1967 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए जसवंत नगर से विधायक चुने गए। उन्होंने वर्ष 1975 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा देश में आपातकाल घोषित किए जाने का कड़ा विरोध किया। आपातकाल के दौरान वह जेल में भी रहे। 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद वह लोकदल की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बने। सियासत की नब्ज जानने की बेमिसाल योग्यता रखने वाले मुलायम सिंह वर्ष 1982 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए चुने गए और और इस दौरान वह वर्ष 1985 तक उच्च सदन में विपक्ष के नेता भी रहे|

भारत के महान नेता श्री राम मनोहर लोहिया के समाजवादी सिद्धांतों पर चलते हुए श्री मुलायम सिंह यादव ने अक्टूबर, 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत की उभरती भूमिका पर अपनी स्पष्ट सोच और नेतृत्व के महान गुणों के चलते नेताजी को 1996 में देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया।

दूरदृष्टा नेताजी ने तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नेताजी ने पिछड़े और गरीब वर्गों का ख़ास ध्यान रखा। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाईं, जिससे उपेक्षित वर्ग के लोग भी आगे बढ़ सकें और समाज का हर तबका खुशहाल हो। नेताजी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी गांवों और कस्बों में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए एक अहम मंच बनी। नेताजी के कुशल नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को समाज के दलित और उपेक्षित वर्ग की तरक्की के लिए लगातार काम कर रही है।

मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव की जोड़ी

1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना के साथ साथ शिवपाल यादव मुलायम सिंह के स्थ साये की तरह रहे। मुलायम और शिवपाल की जोड़ी ने समाजवादी पार्टी को मजबूत स्थिति में ला कर खड़ा कर दिया। यह यही दौर था जब मंडल बनाम कमंडल चल रहा था, सभी सामन्ती शक्तियां एक तरफ थी, जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी के रूप में कम कर रहे थे।

तेरहवीं बहिष्कार

सैफई और इसके आसपास के काफी बड़े क्षेत्र की परंपरा है कि तेरहवीं संस्कार यानि मृत्युभोज की परंपरा का बहिष्कार किया जाता है। इससे गरीब परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ता है, लिहाजा आर्थिक रूप से मजबूत परिवार भी इसे नहीं करतें हैं ताकि समाज के अन्य लोगों को भी इसे करने के लिए बाध्य न होना पड़ा। मृत्युभोज जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का श्रेय जाता है नेताजी के मित्र राज्यसभा सांसद रहे बाबू दर्शन सिंह यादव को। बाबू दर्शन सिंह मुलायम सिंह के संघर्ष के दिनों में बतौर मित्र हमेशा साथ रहे। बाबू दर्शन सिंह को नेता के साथ-साथ समाजसेवी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इसके माध्यम से सबसे पहले इटावा-मैनपुरी, कन्नौज समेत कई जनपदों में दहेज उपरांत भोज और नशा का खुलकर विरोध किया। उन्होंने तेरहवीं के

स्थान पर शांति पाठ कराने का प्रयास किया। काफी संघर्ष के बाद इटावा समेत कई जनपदों में लोगों ने मृत्यु उपरांत भोज के स्थान पर शांति पाठ कराना शुरू किया। वे खुद भी शांति पाठ कराने जाते थे। उन्होंने तेरहवीं पर मृत्युभोज न करने का यादव समाज के बीच अभियान छेड़ा। लोगों ने मृत्युभोज न करने का संकल्प लिया और अब इस क्षेत्र में कोई तेरहवीं पर मृत्युभोज नहीं करता है। तेरहवीं के स्थान पर सिर्फ शांति हवन किया जाता है। लिहाजा मुलायम सिंह यादव की तेरहवी भी नहीं किया जाना था लेकिन सोशल मीडिया में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ब्राहमणों को जिस प्रकार से पूड़ी खिलाये जाने की तस्वीरें वायरल हो रही थी चर्चा का विषय है।

आजमगढ़ और पूर्वांचल के कई जिलों में मुलायम सिंह यादव की श्रधांजलि सभा में लोगों ने तेरहवीं न करने का संकल्प लिया। हालाँकि आजमगढ़ के अम्बरी क्षेत्र में तेरहवीं न करने का प्रचलन पहले से ही चला आ रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव की तेरहवीं की जगह शोक सभा का आयोजन किया गया था। जौनपुर के मडियाहूँ क्षेत्र में शूद्र लाल प्रताप यादव तेरहवीं न किये जाने को लेकर बहुत पहले से अभियान छेड़े हुए हैं।

आजमगढ़ के डढ़िया गांववासियों ने तेहरवीं न करने का संकल्प लिया। कई ऐसे लोग भी रहे जिनके प्रियजनों का निधन उसी अवधि में हुआ जिसमे की नेता जी उनके परिजनों ने भी तेरहवीं नहीं किया|

मुलायम सिंह के लिए प्रचलित नारे

नेता जी मुलायम सिंह यादव के लिए कई सियासी नारे गढ़े गए साथ ही साथ उन्होंने भी कई नारे लगाए, मुलायम ने खुद कई नारे अपनी प्राथमिकताओं को बताने के लिए दिए। इसमें समान शिक्षा के लिए 'शिक्षा होगी एक समान, तभी बनेगा हिन्दोस्तान' जैसा नारा भी है। समाजवादी विचारधारा पर राजनीति करने वाले मुलायम सिंह यादव ने स्वास्थ्य, शिक्षा और आम लोगों के लिए महंगाई को प्राथमिकता बताते हुए 'रोटी-कपड़ा सस्ती हो, दवा-पढ़ाई मुफ्ती हो' का नारा दिया था।

'मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम'

1990 के दशक में जब मंडल बनाम कमण्डल चल रहा था, देश मे ओबीसी आरक्षण लागू हुआ था, जिसकी काट निकालने के लिए रामनाम की राजनीति तेज थी। दोनों बहुजन पार्टियों सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ रही थी। मुलायम और कांशीराम के साथ आने से उत्साहित होकर एक समर्थक ने यह नारा लगाया, उसके बाद ये नारा हिट हो गया।

जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है"

मुलायम ऐसे नेता भी रहे जिनकी लोकप्रियता और कार्यकर्ताओं पर उनके प्रभाव ने भी कई नारों (स्लोगन) को जन्म दिया। मुलायम के सियासी कद को देखते हुए इलाहाबाद के युवा उत्साही कार्यकर्ताओं ने"जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है" का नारा दिया था। साल 2004 में मुलायम सिंह यादव प्रयागराज (उस समय इलाहाबाद) के रामबाग स्थित सेवा समिति विद्या मंदिर के मैदान में मुलायम को सुनने के लिए बहुत भीड़ जमा थी। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर पहुंचा तो भीड़ ने नारा लगाया 'जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है'। भीड़ को देख कर गदगद मुलायम ने मंच में माइक पर पहुंचते ही कहा 'आप सबकी वजह से ही मेरा जलवा कायम है। ' बस फिर क्या था समाजवादी कार्यकर्ताओं खास तौर पर युवा कार्यकर्ताओं ने नारा लगाना शुरू किया।..'जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है'।

नाम मुलायम, काम मुलायम, फिर एक बार मुलायम'

2007 के चुनावी माहौल में ऐसा ही एक और नारा मुलायम के नाम को लेकर बना। चुनावी सभाओं में ये नारा खूब लगाया गया। समाजवादी पार्टी की यूथ विंग के कार्यकर्ता हर सभा में इस नारे को लगाते देखे जा सकते थे।

मन से है मुलायम, इरादे लोहा हैं

ये स्लोगन दरअसल एक गीत की लाइन है जिसे मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी उदय प्रताप सिंह ने लिखा है। गीत में समाजवाद और समाजवादी लोगों के काम थे। लेकिन गीत की ये लाइन 'मन से है मुलायम और इरादे लोहा है' नारे के तौर पर मशहूर हो गया।

संविधान रक्षक मुलायम सिंह

मन से है मुलायम, इरादे लोहा हैं।..यदि यह नारा मुलायम सिंह यादव के लिए बना था तो उन्होंने उसी के अनुरूप काम भी किए। 1990 में उन्होंने अयोध्या में उत्पातियों के साथ सख्ती से निपटने में जरा भी नहीं डगमगाए, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए वो कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटे। देश के अल्पसंख्यक वर्ग को संविधान में विश्वास बनाये रखने के लिए उनकी यह सख्ती जरूरी थी उस समय यदि वह ऐसा नहीं करते तो देश के मुसलमानों का विश्वास टूट जाता।

मुलायम ने हमेशा भारत के लिए पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन को बताया। जब वह रक्षामंत्री थे, तब पाकिस्तान ने उन दो सालों में सीजफायर नहीं किया था। मुलायम के रक्षामंत्री रहते हुए बॉर्डर पर भारतीय सेना ने चीन को चार किलोमीटर पीछे ढकेल दिया था।

सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा वायरल मुलायम की फोटो-

मुलायम सिंह यादव के शब्दों में समाजवादी पार्टी एक ऐसा समाज बनाने में विश्वास करती है जहां समानता के सिद्धांत पर काम हो। पार्टी का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक है। समाजवादी पार्टी समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान की दिशा में लगातार काम करने में विश्वास करती है और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ी है।

मुलायम के बिना सपा

नेताजी मुलायम सिंह यादव के ना होने पर समाजवादी पार्टी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती उसके अपने परंपरागत वोटर्स यादव और मुस्लिम कुछ जुड़े रखना। पिछले कई सालों से सत्ता में ना होने बावजूद भी सपा का परम्परागत वोटरों उसके साथ बना हुआ है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय और शिवपाल यादव के पुनः सपा में आ जाने से हो जाने से सपा की स्थिति मजबूत दिख रही है।

रक्षा मंत्री के रूप में मुलायम

मुख्यमंत्री और फिर रक्षामंत्री के तौर पर उनके कई बड़े फैसले हमेशा याद किए जाएंगे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जिसके कारण सेना ने उन्हें बेस्ट रक्षा मंत्री का आर्डर दिया था। मुलायम सिंह यादव देश के पहले

रक्षा मंत्री थे जो सियाचिन ग्लेशियर पर गए थे। चीन को लेकर मुलायम हमेशा सख्त ही नजर आए। वह कहते थे भारत के लिए पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है। हमें चीन के मुकाबले तैयार होने की जरूरत है। हाल ही में चीन के साथ हुए विवाद के बाद वायरल हो रहे वीडियो में सपा संस्थापक कह रहे हैं, "अगर चीन कमजोर होगा तो चुप बैठेगा और मजबूत होगा तो आपके सामने आ जाएगा। चीन हिंदुस्तान को ही दुश्मन मानता है। नोट कर लो मेरी बात सच है। मैं भी रक्षा मंत्री रहा हूं। मैंने भी चीन को देखा है, उसने एक किमी अंदर फौज भेजी थी, मैंने भी चार किसी अंदर भेज दी|"

"वो हटा ले गए तो हमने भी हटा दी, हमारी फौज कमजोर नहीं है दुनिया में सबसे बहादुर फौज है तो हिंदुस्तान की है इसलिए चीन से सावधान हो जाइए। पूरे सदन को कहना चाहता हूं कि चीन नहीं मानेगा वो किसी ना किसी तरह से हिंदुस्तान पर समस्या पैदा करेगा"।

मुलायम ने हमेशा भारत के लिए पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन को बताया। जब वह रक्षामंत्री थे, तब पाकिस्तान ने उन दो सालों में सीजफायर नहीं किया था। मुलायम के रक्षामंत्री रहते हुए बॉर्डर पर भारतीय सेना ने चीन को चार किलोमीटर पीछे ढकेल दिया था।

मुलायम सिंह यादव के रक्षामंत्री बनने से पहले सेना के लिए अलग नियम था। जब भी

सेना का कोई जवान शहीद होता था, तो उसका पार्थिव शरीर उसके घर नहीं पहुंचाया जाता था। शरीर का अंतिम संस्कार सेना के जवान खुद करते थे और आखिर में जवान के घर उसकी एक टोपी भेज दी जाती थी।

मुलायम सिंह ने रक्षामंत्री बनने के बाद सबसे पहले इसी को लेकर फैसला लिया। उन्होंने कानून बनाया कि जब भी कोई जवान शहीद होगा तो उसका पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ उसके घर ले जाए जाएगा। डीएम और एसएसपी शहीद जवान के पार्थिव शरीर के साथ उसके घर जाएंगे। ▪

जातीय जनगणना रिपोर्ट
ग्राम सभा- छिड़ा, जिला- अमेठी

जातीय जनगणना रिपोर्ट बसावन इंडिया का रेगुलर कालम है। बसावन इंडिया ने उत्तर प्रदेश के 8 जिलों के 8 गांवों का रेंडमली चयन करते हुए जातीय जनगणना के आंकड़ों का प्रकाशन किया है। बसावन इंडिया द्वारा अबतक आजमगढ़ जिले की भरमा-डढ़िया ग्राम सभा, संत रविदास नगर के भक्तापुर ग्राम, अम्बेडकर नगर जिले की सेहरी लहिया ग्रामसभा, महाराजगंज जिले की महादेवा काशीराम, गाजीपुर जिले की खरगपुर, जौनपुर जिले की मुड़ाव और प्रयागराज जिले की पुरे हिंछा ग्राम सभा की रिपोर्ट का प्रकाशन किया। बसावन इंडिया ने अपने इस अंक के लिए अमेठी जिले के छिड़ा ग्रामसभा का चयन किया है। जिसकी रिपोर्ट को छिड़ा ग्राम सभा के चौधरी संदीप यादव ने तैयार की है।

जातीय जनगणना के लिए हम गांव की नवीनतम निर्वाचन सूची को आधार बनाते है, उसी गांव के किसी व्यक्ति द्वारा जातियों को चिन्हित कर जातिवार आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। यदि आप अपने गांव की जनगणना रिपोर्ट का प्रकाशन चाहते हैं तो नवीनतम मतदाता सूची को आधार बनाकर बसावन इंडिया को मेल कीजिए। बसावन इंडिया की संपादकीय टीम यदि आपके गांव की रिपोर्ट का चयन करती है तो सिटिजन जर्नलिस्ट के रूप में आपको क्रेडिट देते हुए आपके फोटो के साथ आपका नाम मैगजीन में प्रकशित किया जाएगा।

छिड़ा ग्रामसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 1343 है। जिसमे कुर्मी, अहीर, चमार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूज, कलवार, नाई, धोबी, लोहार, कोंहार,गड़ेरिया,कहांर, लोनिया सहित कुल 14 जातियां रहती हैं।

छिड़ा ग्रामसभा पिछड़ा बाहुल्य है। पिछड़ी जाति के कुल मतदाताओं की संख्या 1012 है, जो कुल मतदाताओं की संख्या का 75 फीसदी है। पिछड़ी जातियों में सबसे अधिक संख्या 637 कुर्मी मतदाताओं की है। इसके बाद अहीर हैं जिनकी संख्या 156 है। ग्राम सभा में भूज मतदाताओं की संख्या 51, कलवार मतदाताओं की संख्या 48, नाई 31, लोहार 26, कोंहार 21, गड़ेरिया 19 कहांर 16 और लोनिया मतदाताओं की संख्या 7 है।

छिड़ा ग्रामसभा में सवर्ण मतदाताओं में ब्राह्मण & क्षत्रिय मतदाता है जिनकी कुल संख्या 150 है। जो ग्रामसभा की कुल जनसँख्या का 11 फीसदी है। सवर्ण मतदाताओं में सबसे अधिक संख्या ब्राहमणों की है। ब्राह्मणों की संख्या 77 है, जबकि क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या 73 है।

छिड़ा ग्रामसभा में अनुसूचित जातियों में, चमार और धोबी हैं,जिसमें चमार 152 और धोबी 29 हैं जो कुल मतदाताओं की संख्या का 13 फीसदी है। ▪

चौधरी संदीप यादव
मो.न.- 9453318031

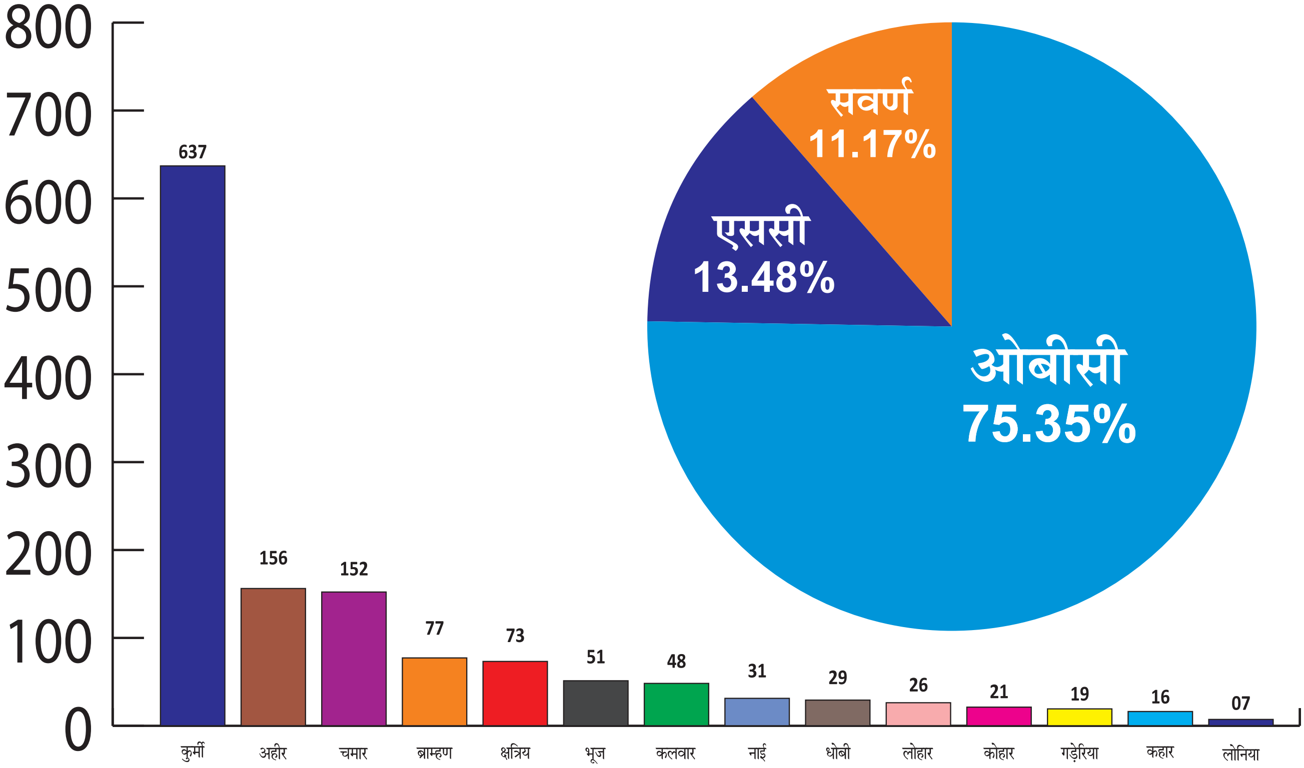

ग्राम पंचायत चुनाव मतदाता सूची 2021 के अनुसार ग्राम सभा- छिड़ा, जिला- अमेठी

यूपी के विश्वविद्यालयों में सवर्ण कुलपतियों का बोलबाला

▪ बसावन इंडिया डेस्क

1981 में बना,89 में घोषणा और 94 में लागू होने के बाद क्या हाल है मंडल का? इसको लेकर बसावन इंडिया मंडल ऑडिट (मंडल लेखा परीक्षण) करने जा रही है। यूपी चुनाव के ठीक पहले भारत सरकार (मोदी सरकार) ने अपने घोषित मंत्रियों का लेखा जोखा सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से करके नया प्रतिमान स्थापित किया। विधानसभा में प्रत्याशियों की सूची में जातिवार ब्यौरा दिया गया। भाजपा सरकार की अच्छी शुरुआत थी। कथित सामाजिक न्याय वादी दलों में जाति जनगणना को लेकर भले ही भ्रम रहा हो लेकिन लेकिन टिकटों में मंडलवाद का कितना रखा और कमण्डलवाद कितना हावी रहा, इसका नीर क्षीर था, साफ सुथरा परीक्षण ऑडिट करने की जरूरत है, जिससे संविधान निर्माताओं की सामाजिक न्याय की चिंता के प्रति न्याय हो सके।

हम भारत के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि सवा सौ करोड़ (2021 की जनगणना होने तक 2011 की जनगणना आकड़े आधारित) देश वासियों को तथ्यपरक और शोधपरक सामग्री के साथ आने का प्रयास बसावन इंडिया टीम ने किया है।

इस बार उत्तर प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों जिसमे राज्य स्तरीय और केन्द्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं,की शोधपरक ऑडिट प्रस्तुत किया जा रहा है। आपका सुझाव और सहयोग आपेक्षित है, जिससे हम शोधपरक पत्रकारिता का नमूना पेश कर सकें।

उत्तर प्रदेश में पांच केन्द्रीय विश्वविद्यालय और 31 राज्य विश्वविद्यालय है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की बात करें तो अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति सवर्ण है। अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तारिक मंसूर उत्तर प्रदेश में स्थित सभी केन्द्रीय और राज्य विश्विद्यालयों में एकमात्र कुलपति हैं जो मुस्लिम हैं।

उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में जातिगत हिस्सेदारी

विश्वविद्यालय	जाति
अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय	मुस्लिम
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	जैन सवर्ण
इलाहबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय	कायस्थ
बी बी ए यू लखनऊ	क्षत्रिय
राजीव गाँधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय	क्षत्रिय

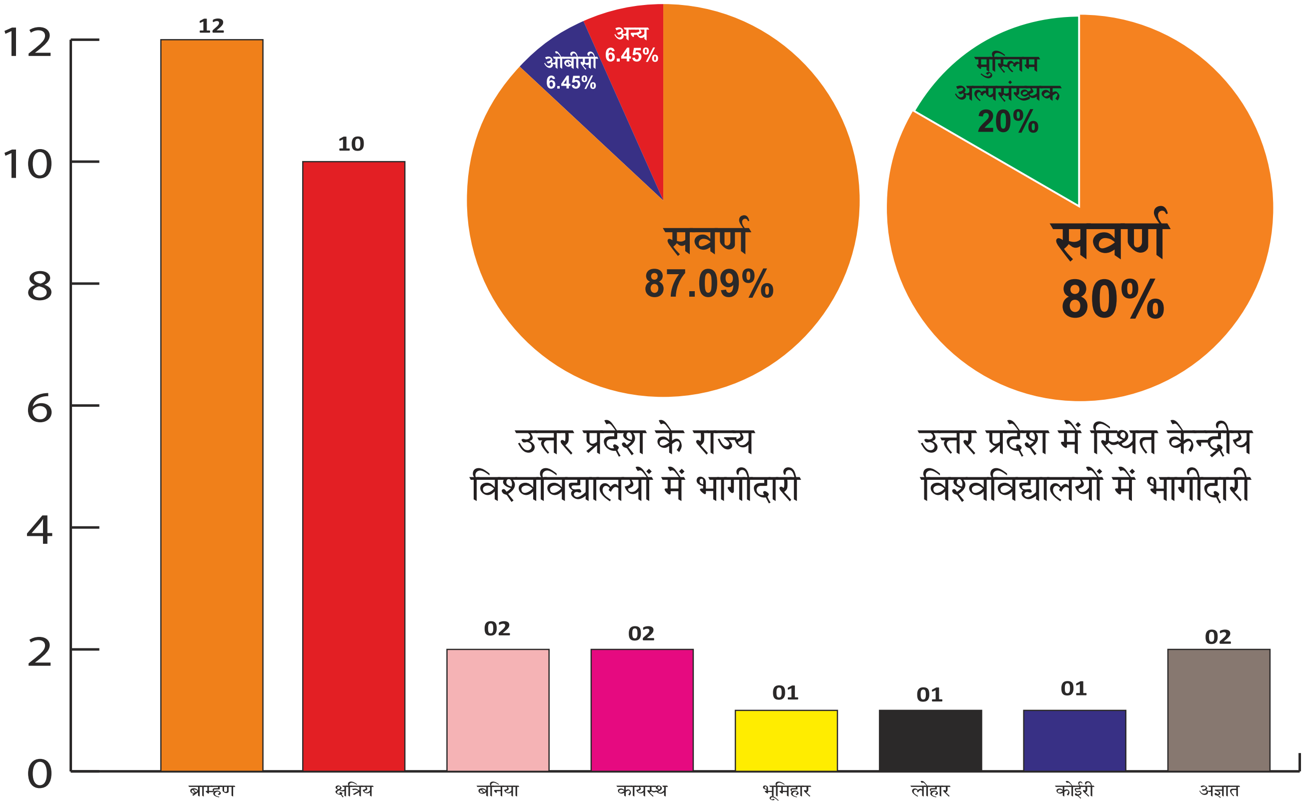

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में भागीदारी

उत्तर प्रदेश में स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भागीदारी

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में जातिवार संख्या

विश्वविद्यालय	कुलपति का नाम	जाति
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झाँसी	प्रो. मुकेश पांडेय	ब्राह्मण
भातखंडे संगीत संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय लखनऊ	रंजन कुमार आई ए एस	ब्राह्मण
छत्रपति साहू जी महाराज विवि कानपुर	प्रो. विनय कुमार पाठक	ब्राह्मण
चौधरी चरणसिंह विवि मेरठ	प्रो. संगीता शुक्ला	ब्राह्मण
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विवि लखनऊ	प्रो. प्रदीप कुमार मिश्रा	ब्राह्मण
जननायक चंद्रशेखर विवि बलिया	प्रो. कल्पना पांडेय	ब्राह्मण
के जी एम यू लखनऊ ले जनरल	डॉ. बिपिन पुरी	ब्राह्मण
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विवि लखनऊ	प्रो. विनय कुमार पाठक	ब्राह्मण
मदन मोहन मालवीय तकनीकी विवि गोरखपुर	प्रो. जयप्रकाश पांडेय	ब्राह्मण
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ वाराणसी	प्रो. आनंद के त्यागी	ब्राह्मण
संपूर्णानंद संस्कृत विवि लखनऊ	प्रो. हरेराम त्रिपाठी	ब्राह्मण
महाराजा सुहेलदेव राज्य विवि आजमगढ़	प्रो. प्रदीप कुमार शर्मा	ब्राह्मण
अटल विहारी वाजपेयी चिकित्सा विवि लखनऊ	प्रो. अरुण के सिंह	क्षत्रिय
बाँदा कृषि एवं तकनीकी विवि बाँदा	प्रो. नरेन्द्र प्रताप सिंह	क्षत्रिय
चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विवि कानपुर	डॉ. डी आर सिंह	क्षत्रिय
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि गोरखपुर	प्रो. राजेश सिंह	क्षत्रिय
डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विवि अयोध्या	प्रो. रविशंकर सिंह	क्षत्रिय
डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विवि लखनऊ	प्रो. आर के पाल सिंह	क्षत्रिय
महात्मा ज्योतिबाफुले रोहिलखंड विवि बरेली	प्रो. के पी सिंह	क्षत्रिय
नरेन्द्र देव कृषि एवं तकनीकी विवि अयोध्या	डॉ. बिजेंद्र सिंह	क्षत्रिय
प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया)विवि प्रयागराज	डॉ. अखिलेश कुमार सिंह	क्षत्रिय
यूपी राजर्षि टंडन मुक्त विवि प्रयागराज	प्रो. सीमा सिंह	क्षत्रिय
सिद्धार्थ विवि कपिलवस्तु सिधार्थनगर	प्रो. एच बी श्रीवास्तव	कायस्थ
यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञानं विवि एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा	प्रो. अनिल कुमार श्रीवास्तव	कायस्थ
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विवि मेरठ	डॉ. आर के मित्तल	बनिया
डॉ. भीम राव अंबेडकर विवि आगरा	प्रो. अशोक मित्तल	बनिया
लखनऊ विश्विद्यालय लखनऊ	प्रो. अलोक कुमार राय	भूमिहार
एस पी जी आईं चिकित्सा विवि लखनऊ	प्रो. आर के धीमान	लोहार (विश्वकर्मा)
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर	प्रो. निर्मला एस मौर्या	कोइरी (मौर्या)
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विवि कानपुर	प्रो. शमशेर	अज्ञात
डॉ. राम मनोहर लोहिया चिकित्सा विज्ञानं संस्थान लखनऊ	प्रो. सोनिया नियानंद	अज्ञात

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों की बात करें तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर एकमात्र विश्वविद्यालय है जहाँ की कुलपति गैर सवर्ण तबके यानि कोइरी जाति से आती है शेष सभी विश्विद्यालयों के कुलपति ब्राहमण, क्षत्रिय, बनिया, लाला और भूमिहार तबके से आते हैं यानि सवर्ण जाति से ताल्लुक रखते हैं।

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में मुसलमान कुलपति नियुक्त किये जाने की बात छोड़िए, मुसलमान तो शुरू से ही हांसिए पर रहा हैं। अहीरों का डर दिखाकर वर्तमान में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी सरकार तथाकथित हिन्दू जातियां धोबी धरिकार लोहार, कन्हार कोहर चमार की हिस्सेदारी तय करनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश के 31 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की जातिवार गणना की जाए तो सबसे अधिक ब्राहमण जिनकी संख्या 12 है, इसके बाद क्षत्रिय जाति के कुलपति हैं जिनकी संख्या 10 है। दो बनिया, दो लाला (कायस्थ), एक भूमिहार, एक मौर्या और एक लोहार (धीमान) जाति से है। (धीमान जाति वैसे तो ओबीसी की जाति है लेकिन कहीं कही अनुसूचित जाति में आती है इनका मुख्य जातिगत पेश लोहे की कारीगरी का है।) दो कुलपति ऐसे रहे जिनकी जाति का पता नही चल सका। कुलपतियों की इस जमात में एक भी कुलपति मुसलमान नही है और न ही अनुसूचित जाति से है।

कुलपतियों की इस जमात में 39 फ़ीसदी ब्राहमण, 32 फ़ीसदी क्षत्रिय, 7-7 फ़ीसदी बनिया और लाला, 3 फ़ीसदी भूमिहार और 7 फ़ीसदी में ओबीसी की दो जातियां शामिल हैं। संपूर्ण भागीदारी की बात करें तो 87 फ़ीसदी पदों सवर्णों का कब्ज़ा है। ▪

इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय में चार सौ फीसदी फीस वृद्धि

▪ **बसावन इंडिया डेस्क**

इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय में चार सौ फीसदी फीस वृद्धि को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें सभी छात्र संगठनों ने हिस्सा लिया है। विरोध पिछलों दिनों इतना तेज हो गया है कि पुलिस ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट में ताला लगा दिया, जिसके बाद छात्रों ने ताला तोड़ दिया। इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय की 400% फीस वृद्धि का मामला, लोकसभा सांसद कोकराझार, असम के सांसद नाबा कुमार सरन ने लोकसभा में उठाया। लगातार सुर्ख़ियों में बने रहने वाले दलित प्रोफेसर डॉ. विक्रम हरिजन भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में हैं। कला संकाय में मध्यकालीन आधुनिक इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विक्रम ने छात्रों का समर्थन किया है, जिससे छात्रों में काफी उत्साह है।

नाराज छात्रों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का घेराव किया। विश्वविद्यालय में आंदोलनरत छात्रों ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जहाँ एक तरफ देश अभी भयंकर कोरोना महामारी से उबरने का प्रयास कर रह था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन कोरोना के समय की फीस को लौटाने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेश को भी नहीं माना और 400% शुल्क कि बढ़ोतरी कर दी गयी।

कोर्स का नाम	पहले (फीस)	अब (फीस)
B.A.	975 रुपए	3701 रुपए
B.com	975 रुपए	3901 रुपए
B.A प्रैक्टिकल	1125 रुपए	3991 रुपए
Bsc.	1125 रुपए	4151 रुपए
M.A.	1375 रुपए	4651 रुपए
B.tec	1941 रुपए	5151 रुपए
L.L.B.	1375 रुपए	4651 रुपए
स्टूडेंट यूनियन	10 रुपए	50 रुपए
कल्चरर प्रोग्राम	20 रुपए	200 रुपए
आइडेंटी कार्ड	20 रुपए	200 रुपए
एथलेटिक्स	10 रुपए	250 रुपए
पूअर फंड	शून्य	500 रुपए
लाइब्रेरी	100 रुपए	500 रुपए
हास्टल	15000 रुपए (वार्षिक)	45,000 रुपए
एग्जाम	1000 रुपए	1500 रुपए
इनरोलमेंट	शून्य	400 रुपए
हेल्थ केयर	शून्य	50 रुपए
ट्यूशन	180 रुपए	600 रुपए
डेवलपमेंट	100 रुपए	1000 रुपए

आंदोलनरत छात्रों ने आरोप लगाया कि इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय कि कुलपति की नियुक्ति अवैध है और उनको तत्काल उनके पद से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बर्खास्त करे। कुलपति की बर्खास्तगी को लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय के 36000 छात्र-छात्राओं के हस्ताक्षर अभियान चलाया जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा और उनकी तत्काल बर्खास्तगी की मांग की।

छात्रों का एक डेलिगेशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव से मिला और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% शुल्क वृद्धि कुलपति की अवैध नियुक्ति और छात्रसंघ बहाली के मुद्दों को लेकर यूजीसी के सचिव को अवगत कराया सचिव ने आश्वासन दिया छात्रों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण होगा और कुलपति की नियुक्ति के खिलाफ जल्द ही कार्यवाही की जाएगी

21 सितंबर 2022 से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के लेकर लगातार चल रहे आमरण अनशन में छात्रों के समर्थन में प्रोफेसर विक्रम धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे। जहां स्टूडेंट्स ने उनके समर्थन के लिए नारे भी लगाए थे। अब इस समर्थन के कारण उन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है।

डॉ. लक्ष्मण यादव
अप्रि. प्रोफेसर, डीयू

“नई शिक्षा नीति ने इस मुल्क़ के वंचित शोषित किसान कामगार मेहनतकश आवाम की संतानों से हमेशा के लिए शिक्षा के मौक़े छीन लिए हैं। इस नीति में फ़ीस बढ़ना, सीट घटना, फ़ेलोशिप न मिलना, शिक्षकों की नौकरी जाना सब तय है। कुछ का असर दिखना शुरू हो चुका है, कुछ आगे दिखेगा। इसकी मार सबसे पहले और सबसे भयावह पहली पीढ़ी के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, प्रोफ़ेसरों व कर्मचारियों पर पड़ेगी। बाक़ी सबका नम्बर कुछ देर बाद आएगा। मगर आपको इसकी चिंता कहाँ है? आपको हिंदू मुस्लिम में मज़ा आ रहा है, आपको किसी नेता की बेहयाई को भी डिफ़ेंड करना है। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय सब तबाह होगा, तभी न हर कहीं शौचालय और देवालय ही बचेगा।”

फीस वृद्धि संविधान विरोधी

जेएनयू प्रशासन ने फीस वृद्धि वापस ली थी

डॉ. विक्रम से मामले में विस्तार से बात की है। डॉ. विक्रम ने बताया कि, यह वह समय है जब स्टूडेंट्स के साथ खड़े होने की जरूरत है। ताकि सस्ती शिक्षा को बचाया जा सके। वह कहते हैं, “यह फीस वृद्धि संविधान विरोधी है। कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रह जाए इसलिए बाबा साहब ने संविधान सभा में शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात कही थी। ताकि एससी/एसटी समाज के बच्चे शिक्षा को ग्रहण कर सकें। इसी को बचाने के लिए ही मैं अपने छात्रों के साथ खड़ा हूं।”

फीस वृद्धि के बाद शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर डॉ. विक्रम का कहना है कि प्रशासन द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि फीस वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं है। प्रोफेसर सवाल करते हुए कहते हैं कि, क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक छात्र की जिंदगी सिर्फ फीस भरना ही है। एक स्टूडेंटस की 100 जरूरतें हैं। “गरीब बच्चे उम्मीद से सरकारी शिक्षा संस्थानों में शिक्षा लेने आते हैं कि पढ़ लिखकर अपनी जिंदगी को बदलेंगे, लेकिन शिक्षा ही महंगी हो जाएगी तो गरीब कहां जाएगा।”

साल 2020 में जेएनयू की बढ़ी फीस का जिक्र करते हुए वह कहते हैं कि अगर वहां फीस वृद्धि वापस हो सकती है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं?

प्रोफेसर के छात्रों के समर्थन में आने के बाद विश्वविद्यालय के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर व प्रोफेसर जया कपूर ने एक स्थानीय समाचार पत्र को दिए अपने बयान में कहा है कि, हमें प्रोफेसर विक्रम के छात्रों के समर्थन के बारे में पता चला है। विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही उनसे इस बारे में संपर्क करेगा और उनका पक्ष जानने की कोशिश करेगा।

प्रोफ़ेसर विक्रम का कहना है कि “ मैं अपने वक्तव्य पर कायम हूं। बिना किसी डर के, मुझसे जब भी इस बारे में कुछ पूछा जाएगा तो मेरा जवाब वहीं होगा जो आज है कि निशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए और फीस वृद्धि वापस होनी चाहिए। ताकि हर कोई शिक्षा को ग्रहण कर आगे बढ़ सके।” ▪

भाजपा के नहले पर भूपेश का दहला

छत्तीसगढ़ देश में सबसे अधिक आरक्षण देने वाला राज्य बना

▪ डॉ. नरेश कुमार साहू

2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव और 2024 ले लोक सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ ओबीसी वोट बैंक पर दांव खेलते हुए छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष तेली जाति के बिलासपुर के सांसद अरुण साव को बनाया। छत्तीसगढ़ में तेली समुदाय की आबादी ओबीसी वर्ग में सबसे अधिक है, उसके बाद पिछड़े वर्ग में कुर्मियों की आबादी मानी जाती है। भाजपा ने ओबीसी की तेली जाति को अपनी तरफ लेन के लिए किया, वहीं छत्तीसगढ़ के कुर्मी जाति से आने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो कदम आगे बढ़ कर संपूर्ण ओबीसी वोटबैंक को साधते हुए आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया। ओबीसी की 27% आरक्षण की मांग को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा में गत 2 दिसंबर, 2022 को राज्य में आरक्षण की सीमा 68 प्रतिशत से बढ़ाकर 76 प्रतिशत किये जाने संबंधी दो विधेयकों को पारित कर दिया गया। अब यदि राज्यपाल द्वारा इन विधेयकों को मंजूरी मिल जाती है तो राज्य में अनुसूचित जनजाति को 32 फीसदी, अनुसूचित जाति को 13 फीसदी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण राज्याधीन सेवाओं व उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक आधार पर कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए दिये गये 10 फीसदी आरक्षण को 6 फीसदी घटाकर 4 फीसदी कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ देश में सबसे अधिक आरक्षण देने वाला राज्य बन गया है।

हाई कोर्ट ने लगा दी थी आरक्षण पर रोक

गौर तलब है कि गत 19 सितंबर, 2022 को बिलासपुर हाई कोर्ट ने राज्य में आरक्षण के अनुपालन पर रोक लगा दी थी। इसके पहले सूबे में 68 प्रतिशत आरक्षण था। इनमें से अनुसूचित जाति को 12 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को 32 फीसदी, अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण था। हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण पर लगाए गए रोक को हटाने के लए राज्य सरकार ने यह पहल की।

मील का पत्थर साबित होगा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण विधेयक पर कहा कि सारे लोगों के प्रयास से बनाया गया है, यह मील का पत्थर साबित होने वाला है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास जाकर अनुरोध करने का भरोसा दिलाते हुए विपक्ष से भी मदद मांगी। उन्होंने कहा कि आरक्षण में किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा गया है, चूंकि 2021 में जनगणना होने वाली थी, मगर वह ड्यू है, जैसे ही जनगणना प्रारंभ होगा, उसके मुताबिक आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि भी करेंगे।

विधेयकों के पारित होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि "छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने वाले दो नये विधेयकों को बहुमत से पारित कर दिया है।

-शेष भाग-34 में

केन्द्रीय सेवाओं में पिछड़ों को नहीं मिल सकी है उनकी हिस्सेदारी

केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को मिलने वाले 27 फीसदी आरक्षण की तुलना में समूह ए पदों पर उसकी हिस्सेदारी महज 16.08 फीसदी तक पहुंच पाई है। कार्मिक मंत्रालय की हाल में जारी वार्षिक रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आया है। केंद्रीय सेवाओं में कुल 49,638 पदों में से 7,980 पदों पर ओबीसी कार्मिक हैं, जबकि समूह बी के पदों यह और भी कम 13.64 फीसदी है। 1,48,365 पदों में से 20,234 पदों पर ओबीसी कार्मिक हैं। समूह ग के पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा 21.22 फीसदी है। इसी श्रेणी में सफाई कर्मियों में उनकी हिस्सेदारी 17.39 फीसदी है। यदि केंद्र सरकार के सिर्फ ग्रुप ए पदों पर आरक्षण की बातें करें तो अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 14.41 फीसदी है। यह उसको मिलने वाले आरक्षण से दो गुनी है। केंद्र सरकार में ग्रुप ए के कुल 49,638 पद हैं जिनमें से 7, 151 पर एस सी की हिस्सेदारी है। इसी प्रकार ग्रुप बी के पदों पर भी एस सी की हिस्सेदारी 16.65 फीसदी दर्ज की गई है। कुल 1,48,365 पदों में से 24,707 पदों पर एस सी कार्मिक तैनात हैं। समूह सी के पदों पर एससी कार्मिकों का प्रतिशत 16.99 फीसदी है।

मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म 1 अक्टूबर 1919 को सुल्तानपुर जिले में हुआ एक भारतीय उर्दू शायर थे। हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार और प्रगतिशील आंदोलन के उर्दू के सबसे बड़े शहरों में से एक थे। बीसवीं सदी के उर्दू साहित्य जगत के बेहतरीन शायरों में गिना जाता है। बॉलीवुड के गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए देश समाज और साहित्य को नई दिशा देने का काम किया। मजरूह सुल्तानपुरी ने 50 से ज्यादा सालों तक हिंदी फिल्मों के गीत लिखे। आज़ादी के दो साल बाद एक मुशायरे में हिस्सा लेने गए मजरूह सुल्तानपुरी को सबसे पहले फिल्म शाहजहां के लिए गीत लिखने का अवसर मिला। गम दिए मुस्तकिल और जब दिल ही टूट गया उनके पहले गीत थे जो आज भी लोकप्रिय हैं।

पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीतियों के खिलाफ एक जोशीला गीत लिखने के कारन उन्हें लगभग 15 महीने जेल में भी रहना पड़ा। 1994 में उन्हें फ़िल्मी जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक वे फिल्मो से जुड़े रहे 24 मई 2000 को उनका निधन हो गया।

सुल्तानपुर : सामाजिक न्याय की नई उर्वर भूमि

▪ बसावन इंडिया डेस्क

अयोध्या और प्रयाग के मध्य गोमती नदी के दोनों ओर सई और तमसा नदियों के बीच कभी यह भूभाग अत्याधिक दुर्गम था। गोमती के किनारे का यह क्षेत्र कुश-काश के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है,कुश-काश से बनने वाले बाध की प्रसिद्ध मंडी यही पर है। कुश और काश का प्रयोग कलात्मक वस्तुए बनाने में होता है। जबकि बाध का उपयोग चारपाई बनाने और बाधने के लिए किया जाता है। प्राचीन काल मे सुलतानपुर का नाम कुशभवनपुर था जो कालांतर मे बदलते बदलते सुलतानपुर हो गया।

बसावट

सुल्तानपुर की बसावट को समझना हो तो वहां के बोली-भाषा और नामों पर ध्यान देना होगा। प्रत्येक नाम के पीछे कोई न कोई कारण होता है, नाम रखे जाने के पीछे एक कहानी होती है। सुल्तानपुर दुर्गम क्षेत्र रहा है, बसावट की प्रक्रिया में इस क्षेत्र में यायावर जातियां बसी होंगी जिनमे चरवाहे और पशुपालन से सम्बंधित जातियां रही होंगी। कई बार बसनेके क्रम में उन स्थानों का नाम कारण भी लोगों ने अपने हिसाब से किया होगा। फरीदीपुर, कादीपुर, कुड़वार, अमहट, रतनपुर, बारी सहिजन, कूरेभार, कन्धईपुर सैदखानपुर, लौहर पश्चिम, नानेमऊ, बेलहरी, बिजेथुआ, दियरा, धम्मौर, पीलिया, मलाकतुलापुर, सकरसी, शिवगढ़, चंदा, प्रतापुरकमैचा, तिरहुत, रवनिया, सेमरी, ठठेरी बाजार इत्यादि सुल्तानपुर के गावों या मुहल्लों के नाम है। जो आम बोल चल की भाषा में इस्तेमाल होने वाले बिल्कुल देशज भाषा के शब्द हैं।

इतिहास

मोहम्मद गोरी के आक्रमण के पूर्व यह राजभरो के आधिपत्य मे था,जिनके जनपद मे तीन राज्य इसौली,कुलपुर व भादर थे,आज भी उनके किलों के भग्न अवशेष विद्यमान हैं,जो तत्कालीन गौरव व समृद्धि को मुखरित करते है। बौद्धकालीन दस गणराज्यों में से एक केशिपुत्र के भग्नावशेष आज भी गढ़ा गांव में मौजूद हैं। यहां बुद्ध ने छह माह तक प्रवास किया था और यहां बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। जब बुद्धवाद शिखर पर था तो केशिपुत्र उत्तर भारत के दस बौद्ध गणराज्यों में से एक था। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अभिलेख, बौद्ध सूत्र व स्थानीय परम्पराएं इसकी पुष्टि करते हैं। तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ तक केशिपुत्र समृद्धिशाली नगर था। बौद्धग्रंथ “अंगुत्तर निकाय” व “कलाम सुत पिटक” के अनुसार बुद्ध ने यहां छह माह तक प्रवास कर उपदेश दिया था। आज ये स्थल वर्तमान कुड़वार के गढ़ा गांव में आठ किलोमीटर के क्षेत्र में खंडहर के रूप में विद्यमान है।

1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में केंद्रीय सांस्कृतिक सचिव पुपुल जयकर के निर्देश पर गढ़ा के नाम से विख्यात इस खंडहर को भारतीय पुरातत्व

सुल्तानपुर जिला सामाजिक न्याय की नई उर्वर भूमि के रूप में उभर रहा है। ग्रामीणों द्वारा जन चेतना फ़ैलाने के उद्देश्य से जगह जगह चेतना मंडलीय बना कर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे है, सामाजिक चेतना मंच जागरूक लोगों के द्वारा अंधविश्वास पाखण्ड के खिलाफ बहुजन महापुरुषों के विचारों को बताकर जागरूक किया गया। सुल्तानपुर जिले के कादीपुर क्षेत्र में हमजापुर पठान ग्राम रामशंकर यादव, पारस नाथ पाल, शीतला प्रसाद वर्मा, संग्राम यादव, रामनारायन बौद्ध, अखिलेश यादव, केदारनाथ व अन्य ग्राम वासियों द्वारा व्यापक स्तर पर कार्यक्रम चलाये जा रहा है।

सर्वेक्षण विभाग ने अधिग्रहीत कर लिया। खनन में बौद्धकाल की मूर्तियां, बर्तन आदि प्राप्त हुए जिससे स्थल की ऐतिहासिकता की पुष्टि हुई। जनरल कनिंघम ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है।उन्होंने लिखा है कि उनके समय में यहाँ पर अशोक के द्वारा निर्मित बड़े स्तूप स्थित थे |

राष्ट्रीय चेतना के विकास मे सुलतानपुर का ऐतिहासिक योगदान रहा है। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम मे क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेकने मे जान की बाजी लगाकर अंग्रेज़ो से मोर्चा लिया। सन 1921 के किसान आंदोलन मे इस जनपद ने खुलकर भाग लिया। किसान नेता बाबा राम चंद्र और बाबा राम लाल इस संदर्भ मे उल्लेखनीय है, जिनके त्याग का वर्णन पं. जवाहर लाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा मे किया है ।

सुलतानपुर सड़क के द्वारा गौरीगंज (अमेठी) से भी जुड़ा है।

रमाशंकर यादव विद्रोही का जन्म 3 दिसंबर, 1957 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत अहिरी फिरोजपुर गांव में हुआ उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। सुल्तानपुर में उन्होंने स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने कमला नेहरू इंस्टीट्यूट में वकालत में दाखिला लिया। वे इसे पूरा नहीं कर सके। उन्होंने 1980 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर में प्रवेश किया। 1983 में छात्र आंदोलन के बाद उन्हें जेएनयू से निकाल दिया गया। इसके बावजूद भी वे आजीवन जेएनयू में ही रहे। 8 दिसंबर 2015 को उनका निधन हो गया।

विद्रोही मुख्यत: प्रगतिशील चेतना के कवि हैं। उनकी कविताएं लंबे समय तक अप्रकाशित और उनकी स्मृतियों में सुरक्षित रही। वे अपनी कविता सुनाने के अंदाज के कारण बहुत लोकप्रिय रहे। 2011 में इनकी रचनाओं का प्रकाशन 'नई खेती' शीर्षक संग्रह से हुआ।

प्रस्तुत है उनकी कविताओं का कुछ अंश –

नई खेती

मैं किसान हूँ
आसमान में धान बो रहा हूँ
कुछ लोग कह रहे हैं
कि पगले! आसमान में धान नहीं जमा करता
मैं कहता हूँ पगले!
अगर ज़मीन पर भगवान जम सकता है
तो आसमान में धान भी जम सकता है
और अब तो दोनों में से कोई एक होकर रहेगा
या तो ज़मीन से भगवान उखड़ेगा
या आसमान में धान जमेगा।

औरत

इतिहास में वह पहली औरत कौन थी,
जिसे सबसे पहले जलाया गया,
मैं नहीं जानता,
लेकिन जो भी रही होगी,
मेरी माँ रही होगी।
लेकिन मेरी चिंता यह है कि
भविष्य में वह आख़िरी औरत कौन होगी,
जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा,
मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी
मेरी बेटी होगी, और मैं ये नहीं होने दूँगा

अनुसंधान केवल थीसिस या पुस्तक के रूप में केवल पुस्तकालय का हिस्सा नहीं होना चाहिए

बसावन इंडिया राष्ट्रीय मासिक के बसावन शख्सियत में इस बार देश के जाने-माने शिक्षाविद एवं चिंतक प्रोफ़ेसर डॉ.के.पी.यादव जो कि वर्तमान में मेट्स यूनिवर्सिटी रायपुर (छत्तीसगढ़) के कुलपति है। इस बड़े हस्ताक्षर से साक्षात्कार किए है, बसावन इंडिया के सह-संपादक डॉ.नरेश कुमार साहू के साक्षात्कार के महत्तवपूर्ण अंश-

- **भारत में सबसे अधिक युवाओं की आबादी है? कैसी शिक्षा दी जाए जिससे युवाओं का कैरियर बेहतर बन सके।**

जो शिक्षा होनी चाहिए व रोजगारोन्मुखी होनी चाहिए। शिक्षा के साथ-साथ, उद्यमशीलता, रोजगारपरक हो, चाहे स्व-रोजगार हों, सरकारी एवं प्राइवेट नौकरी में हों उन सभी के अनुसार ग्रेजुशन या अंडर ग्रेजुएशन में प्रशिक्षण दिया जाना बेहद जरुरी है। सभी छात्र -छात्राओं को जब तक सही प्रशिक्षण नहीं होगा या यूँ कहे केवल शिक्षण से देश का विकास संभव नहीं होगा। भारत में शिक्षण के साथ प्रशिक्षण भी बहुत जरुरी है। रोजगार के दिशा में सरकार के साथ -साथ जो इण्डस्ट्रीज है उसको भी सार्थक प्रयास करने होंगे। साथ ही जो युवा वर्ग है उसको भी इस दिशा में लगातार सोंचने व प्रशिक्षण करने की जरुरत है।

- **नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षण होने की बात कही जा रही है,इसे आप कैसे देखते हैं।**

शिक्षा मातृभाषा में होने से सीखना और समझना व शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों आसान हो जाते हैं। हर बच्चे की स्वाभाविक समझ अपनी मातृभाषा में अधिक होती है, लेकिन जहाँ तक उच्च शिक्षा की बात करें या शिक्षा की वैश्विक फलक पर बात करे तो पूरे विश्व में इंलिश का महत्त्व सबसे अधिक है। जितने भी हमारी बढ़िया पुस्तकें है, जर्नल्स रिसर्च जर्नल्स या रिसर्च आर्टिकल्स है, ज्यादातर इंग्लिश में प्रकाशित होते हैं। इसलिए मातृभाषा के साथ-साथ इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है।

- **भारत के विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान दुनिया के टॉप वैश्विक शैक्षणिक संस्थाओं सूची में नहीं आते है, साथ ही शोध की गुणवत्ता को लेकर यहां की शिक्षा पद्धति को लेकर प्रश्न उठता रहता है, इसमें कैसे सुधार किया जाए।**

जहाँ तक मैं समझता हूँ,अभी तक जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है शिक्षण व प्रशिक्षण सिस्टम थोयोरोटिकल अधिक है, प्रेक्टिकल कम है, प्रेक्टिकल भाग को पिछले कुछ समय से समाहित करने की कोशिश की जा रही है।जो भी अनुसंधान हो रहा है उसे यूजीसी या अन्य माध्यम से यह कहा जा रहा है कि इसका कोई न कोई एप्लीकेशन पार्ट होना चाहिए जो कि व्यवहारिक है। अनुसंधान केवल थीसिस के रूप या किताब के फार्मेट में केवल लाइब्रेरी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने जो अनुसंधान किया है या हमारे शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान हुए है अभी भी वैश्विक स्तर के अनुसंधान नहीं हो पाया है। इसमें बहुत कुछ बदलाव किया जाना बहुत जरुरी है।सबसे जरुरी है कि शिक्षण -प्रशिक्षण में, हायर एजुकेशन में,रिसर्च लाइब्रोटरीज के लिए बजट को भी बढ़ाया जाए। नए-नए उपकरण एवं तकनीक लाया जाए उसमें हमारे छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाए, साथ ही साथ प्रोफ़ेसर या एक्सपर्ट भी अपना लगातार मेहनत करें ताकि वैश्विक स्तर पर जैसे कभी हमारे नालंदा,तक्षशिला विश्वविद्यालय नाम भारत का था विश्व में था।

- **आपने विदेशों में पढ़ाई की है, विभिन्न देशों की एजुकेशन सिस्टम को करीब देखें है, भारत की पढ़ाई व विदेश की पढ़ाई में क्या फर्क दिखता है? कैसे यहाँ की एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके.**

इसमें मेरा अनुभव कहता है हमारे देश का जो शिक्षण- प्रशिक्षण में पुस्तकी ज्ञान ज्यादा है। हम किताबों पर आधारित ही ज्यादा काम करते हैं बजाए की प्रैक्टिकल ओरिएंटेड या इण्डस्ट्रीज ओरिएंटेड के हमारा उतना एक्सप्रोजर नहीं है जबकि विदेशों में पुस्तकी ज्ञान के बजाए प्रैक्टिकल ओरिएंटेड या इण्डस्ट्रीज ओरिएंटेशन पर ज्यादा फोकस रहता है। हर चीज को वह सामने प्रमाणिक रूप से देखकर वहां के स्टूडेंट्स समझते हैं इस कारण से प्रमाणिक रूप से इसका असर पड़ता है,स्टूडेंट्स को प्रमाणिक ज्ञान से साथ उनका मनोबल बढ़ता है और किसी चीज को करने को लेकर हिम्मत भी बढ़ता है। लर्निंग प्रोजेक्ट की हमारे यहाँ कमी है मुझे लगता है इस दिशा में शिक्षण संस्थान प्रोजेक्ट बेस और एक्स्पेरिमेंटल लर्निंग पर काम करेंगे तो हमारे देश भी विदेशों की तरह पढ़ाई में निश्चित रूप से समकक्ष बेहतर हो जाएंगे.

- **भारत में बेहतर शोधकार्य या शोध जर्नल्स नहीं होने की बात लगातार सुनने को मिलता है, कैसे बेहतर शोध जर्नल्स निकाले या शोध-कार्य को बढ़ावा ताकि शोधकर्ता को बेहतर जर्नल्स व प्रकाशन का लाभ हमारे यहाँ मिल सके।**

भारत में अभी एडवांश रिसर्च की कमी है।डिफेन्स के क्षेत्र में भी हम बहुत सारी चीजें आयात करते हैं,इसी के साथ मेडिकल के क्षेत्र में भी बहुत से मेडिसीन व रिसर्च हम अन्य देशों से आयात करते हैं,आज हमारा रुपए की कीमत डालर के मुकाबले घट गया है इसमें कहीं न कहीं आयात -निर्यात के बैलेंस का सही नहीं होना भी इसका प्रमुख कारण यह है। यह साफ़- साफ़ दिखता है कि हम आयात ज्यादा कर रहें हैं और निर्यात कम कर रहें है। इसी तरह से रिसर्च को देखे तो अच्छे रिसर्च जर्नल्स की भारत में अभी कमी है, ऐसा नहीं है कि भारत में टेलेंट की कमी है भारत में दुनिया के बेहतर बौद्धिक लोग भारत में है, इसके तमाम उदाहरण है लेकिन जो संसाधनों की जरूरत है उनको शायद हमने समय रहते ध्यान नहीं दिया है। अब समय आ गया है भी रिसर्च से जुड़े लोग शोध के लिए उच्च शिक्षण संस्थान जो भारत में हैं,उन सबको मिलकर इस दिशा में प्रयास करना चाहिए और शोध के जर्नल्स स्थापित करना चाहिए जो दुनिया में अव्वल स्थान पर आते हों. तभी देश का नाम विदेशों में और वैश्विक स्तर पर होगा। ▪

नशे की गिरफ्त में आदिवासी समाज

पूरे विश्व में 50 करोड़ अर्थात् 5 प्रतिशत, देश में 18 करोड़ अर्थात् 8 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ राज्य में 90 लाख अर्थात् 32 प्रतिशत आदिवासी समुदाय की संख्या है। इसी तरह विश्व में कुल क्षेत्रफल के 20 फीसदी, देश में 40 फीसदी और छत्तीसगढ़ राज्य में 65 फीसदी भू-भाग में आदिवासी समुदाय निवासरत है। जहां अकूल धन सम्पदा, जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन है। राज्य में 2.86 करोड़ आबादी है। इसमें से 32 प्रतिशत अर्थात् 92 लाख आदिवासी समुदाय है।

विश्व समुदाय द्वारा 1993 में आदिवासियों के सम्मेलन में आदिवासी समुदाय की पर्यावरणीय संरक्षण में अहम एवं अति महत्वपूर्ण भागीदारी के मद्देनजर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया है। पिछले चार-पांच साल से विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को इंज्वाय करने की दिशा में सम्पूर्ण आदिवासी समाज में उत्कट उत्साह देखने को मिला है। जहां केवल सांस्कृतिक आयोजन और नाचगान होता है। आदिवासी हितों के संरक्षण, संवर्धन के लिये पूरे देश के सभी राज्यों में अनेक योजनाएं, कार्यक्रम, परियोजनाएं संचालित है। कल्याणकारी और विकास कार्यों से आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर सभ्य समाज के समान विकास की मुख्य धारा में लाने का सतत् प्रयास जारी है। आदिवासियों का शोषण न हो, मानव अधिकारों की रक्षा हो, भेदभाव से मुक्त समाज हो, इसके लिए अनेक प्रयोग किया जा रहा है। ताकि सभ्य समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर आदिवासी समुदाय भी अन्य समाज की तरह गरिमामय जीवन यापन कर सके। अभी हाल में ही प्रदेश की राजधानी रायपुर में आदिवासी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जोर-शोर से किया गया। जहां पूरे देश से आदिवासी समुदाय के विचारक, चिंतक और समाज सेवक सहित नेतागण एकत्र हुए। इस सम्मेलन के माध्यम से आदिवासी समुदाय में चेतना जागृत करने और विकास के पथ पर अग्रसर होने का संदेश दिया गया। अनेक विचारकों ने समाज में व्याप्त शोषण, भेदभाव और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली अड़चनों से निपटने हेतु आदिवासी समुदाय को एकजुट होने का संदेश दिया गया। किन्तु जैसा कि हमेशा होता है सम्मेलन का स्याह पक्ष यह था कि आदिवासी समुदाय का एक धड़ा सम्मेलन से गायब था। इसकी मुख्य वजह राजनीतिक दलों से जुड़े हुये नेताओं को सम्मेलन का नेतृत्व सौंपा जाना।

आदिवासी समुदाय अति पिछड़े क्षेत्रों में निवासरत होने से इस तरह के आयोजकों को आपसी तालमेल और भेदभाव को भूलाकर संपूर्ण समाज को एक इकाई के रूप में जोड़ने की जरूरत आज की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। भविष्य में यही स्थिति रही तो समाज की उन्नति में आदिवासी समुदाय स्वयं बाधक होंगे। इससे किसी भी शासन प्रशासन को दोष देना बेमानी कही जा सकती है।

दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में 18 विषयों जिनमें मुख्य विषय विकास की आधुनिक अवधारणा में आदिवासी एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, राष्ट्रीय जनजाति नीति की वर्तमानस्थिति, भूमि अधिग्रहण, पेशा कानून, वन अधिकार, पदोन्नति में आरक्षण, आदिवासी महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार, आदिवासी अत्याचार निवारण अधिनियम का पालन, जनगणना में आदिवासियों की पृथक पहचान एवं संख्या, आदिवासियों पर अत्याचार और शोषण, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासियों पर हो रहे जुल्मों पर विस्तृत चर्चा कर समस्या निदान की दिशा और दशा तैयार करने की रणनीति बनाई गई। सम्मेलन कितना सफल रहा यह बात तो भविष्य के गर्भ में है।

आदिवासी समाज की असल समस्या अशिक्षित और नशायुक्त समाज है। अशिक्षा और नशा के मकड़ जाल से जब तक समाज को मुक्ति नहीं मिलेगी। अधिकार युक्त, शोषण मुक्त और अत्याचार मुक्त समाज की कल्पना करना संभव नहीं है। आदिवासी हमेशा अपने अधिकारों की मांग करते रहते हैं। लेकिन अशिक्षित और नशा से ग्रस्त होने से अधिकारों से भी वंचित होना पड़ता है और सामाजिक वंचना का शिकार बनते रहते हैं। आदिवासी समुदाय के शिक्षित वर्ग समाज में शिक्षा के प्रति, अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा शोषण और अत्याचार के विरूद्ध संघर्ष करने के बजाए शासकीय सेवा अथवा किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल होना अधिक पंसद करते हैं। दुर्भाग्य है कि कदाचित शिक्षित वर्ग स्वार्थवश अपने समुदाय के हितों का संरक्षक होने के बजाए, भक्षक अधिक नजर आते हैं। आदिवासी समुदाय शिक्षित वर्ग से अपेक्षा करता है कि समाज को शिक्षित करें, उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करें, और सही मार्गदर्शन करें। यह भी दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि नेतृत्वकर्ता समाज को सही दिशा देने के बजाए प्रतिनिधित्व के दायित्वों का निर्वहन के बजाए खानापूर्ति की जाती है। कतिपय नेतृत्वकर्ताओं को राजनीतिक दलों के चूल्हें की लकड़ी की तरह जलकर खाख होने पर अहसास होता है कि समाज को शिक्षित, संगठित और नशामुक्त करने की दिशा में उन्हें काम करना चाहिए था। कहावत है अब पछताये होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।

आदिवासी समाज के जिन शिक्षित लोगों को शासकीय सेवा में आने का अवसर मिला है, उनमें से 95 फीसदी या तो नेता बनने का सपना पाल लेते हैं या नशा को अपना साथी बना लेते है, आने वाली पीढ़ी के साथ स्वयं भी इस मृगतृष्णा और लालसा से बर्बाद हो जाते हैं। इसी तरह आदिवासी समाज के नेता समाज का नेतृत्व तो कर रहे हैं लेकिन नेतृत्व में वो ओज,

चमक, दमदारी अथवा धार नहीं है, जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है। आदिवासी समुदाय के अधिकांश लोग राजनीतिक दलों के चूल्हें की लकड़ी बनकर रह जाते हैं, जब तक ऊर्जा है, तब तक दल हित में काम करते है और समाज को नेतृत्व का झुनझुना दिखाते फिरते हैं। जब जलकर राख हो जाते है तब आदिवासी समाज उनको याद आती है। आदिवासी समाज में दबाव गुट का नितांत अभाव भी है। नेतृत्वकर्ताओं के बीच समाज को लेकर बे स्वाद खिचड़ी पक रही है, जिससे समाज का भला होने के बजाए .....कुछ और ही हो रहा है। आदिवासी समाज के शिक्षित वर्ग जिन्होंने शासकीय सेवा ग्रहण किया और संस्कृति, प्रथा के नाम से कानूनी मान्यता प्राप्त आबकारी नीति को नहीं अपनाया, उनकी अगली पीढ़ी अब सभ्य समाज से कदम से कदम मिलाने की स्थिति में है।

अशिक्षित और नशा में डूबा हुआ समाज कभी विकास नहीं कर सकता। शोषण और अत्याचार से मुक्त हो, ये कैसे संभव हो सकता है। जागरूक और शिक्षित समाज ही सभ्यता के शिखर तक पहुंच सकता है। शिक्षित और नशा विमुक्त समाज में शांति व्यवस्था, स्वस्थ्य संगठित सुदृढ़ समाज की कल्पना की जा सकती है। शिक्षा शेरनी का वह दूध, जो पीता है, वह दहाड़ता है। नेतृत्वकर्ताओं ने समाज हित को दरकिनार कर स्व हित को सर्वोच्च मान लिया और नशा, महुआ शराब, हड़िया और लांदा को कानूनी बल देकर पूरे आदिवासी समाज के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है।

हाल में बस्तर की आदिवासी महिलाओं ने परंपरागत हाट बाजारों में खुले आम महुआ की शराब बिक्री पर स्वयं संज्ञान लेते हुए प्रतिबंध लगाने हेतु सड़कों पर उतर आई है। शराब के घातक परिणामों के प्रति जागरूकता का प्रतीक है, समाज में शुचिता के लिए शराब बंदी आवश्यक भी है। समाज में बढ़ती हुई अराजकता से सभी भयाक्रांत है, जिससे सामाजिक सौहार्द्र और सौम्यता समाप्ति के कगार पर है, जिन समाज में नशा व्याप्त हो, उनके कल्याण, प्रगति और विकास के सारे प्रतिमान मूल्यहीन साबित होते हैं। नशा की बुराई को समाप्त करने की पहल आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं की ओर से की जाना सराहनीय है। इस कदम से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इससे ही शिक्षित और नशामुक्त आदिवासी समाज की अवधारणा के सपने को पूरा किया जा सकता है।

हाल ही में देश में नशाखोरी और शराब की खपत का एक सर्वे रिपोर्ट जारी हुआ, इसमें दुर्भाग्य जनक पहलू यह है कि हमारा प्रदेश देश में अव्वल है। 34 फीसदी लोग शराब का सेवन करते हैं। राज्य में हत्या, बलात्कार, मोटर दुर्घटनाएं, चाकूबाजी, युवाओं की असमय मौत के पीछे का सबसे अहम कारण शराब की लत है। राज्य गठन के बाद से ही शराब बंदी बड़ी चुनौतीपूर्ण रहा है, कभी आदिवासियोंकी प्रथा और संस्कृति संरक्षण के नाम पर तो कभी नशा के आदी व्यक्तियों के अधिकारों को लेकर शराब बंदी पर ठोस पहल नहीं की जा सकी है, नशा के आदी व्यक्ति स्वस्थ्य, गरिमामय जीवन जीने से असमय वंचित हो जाता है जिसका दुष्परिणाम महिलाओं को ही सर्वाधिक भुगतना पड़ता है।

आज आदिवासी समुदाय ''महुआ'' के नशे में झूमता हुआ इंसान के रूप में नजर आने लगा है। वह इंसान महुआ छाप इंसान है। एक दिन मैं थोक फल मार्केट गया, वहां मैंने 15 किलो सेब की एक पेटी खरीदी और जल्दी गांव पहुंचने की बात कही। दुकानदार ने मुझे पूछा कहां जल्दी जाना चाहते हैं आप, मैंने उन्हें जैसे ही गरियाबंद जाने की बात कही उन्होंने झट से मुझसे सवाल द्वारा गरियाबंद तो आदिवासी क्षेत्र है। मैंने गर्व से कहा हां मैं वहीं का निवासी हूं और आदिवासी हूं। उन्होंने मुझे तपाक से पूछ लिया तब तो साहब ''महुआ'' बहुत चलता होगा। इतना सुनते ही मैंने भी उन्हें माकूल जवाब दिया ''महुआ'' बहुत चलता है तभी तो मैं आपकी दुकान से प्रतिमाह तीन से चार हजार का फल खरीद लेता हूं। दुकानदार को वास्तविकता का ज्ञान हो गया। उसे अपनी गलती का अहसास हुआ। मुझे उनके इन प्रश्नों ने अंदर से हिलाकर रख दिया। सोचने पर विवश कर दिया कि आदिवासी का पर्यायवाची शब्द महुआ, हड़िया, लांदा हो चुका है। एक दूसरी घटना का जिक्र करना भी समीचीन होगा। मैं और एक अन्य आदिवासी अधिकारी एक साथ एक बैठक में शामिल थे। उनसे एक सामान्य वर्ग के अधिकारी ने बैठक में एक मामले की जानकारी ली, तो वह अधिकारी जानकारी देने में असमर्थ रहा। इतने में सामान्य वर्ग के अधिकारी ने ताना कसते हुये कहा कि आपके ऑफिस के आसपास बहुत अधिक मुहुआ का पेड़ है क्या ? मैं आग बबुला हुआ लेकिन उस निरूतर अधिकरी का मैं चाह कर भी साथ नहीं दे पाया, जिसका मुझे हमेशा ग्लानि रहेगी। अतएव आदिवासी समाज के शिक्षित वर्ग, नेतृत्वकर्ता, सामाजिक विचारक, चिंतक, समाज सेवकों और मांझी मुखियाओं से विनम्र अपील करता हूं आपसी भेदभाव को भूलकर जिन आदिवासी समुदाय ने नशा को त्यागने का संकल्प लिया है उन क्षेत्रों से आबकारी नीति को समाप्त करने की पहल करें और समाज को शिक्षित और नशा से मुक्त करने की दिशा में अपनी ऊर्जा लगाये। ▪

तोरन लाल ध्रुव
मानव अधिकार कार्यकर्ता
मो. 7000194363

पेज 29 का शेष भाग

इसे राज्यपाल को भेजा गया है। उनके हस्ताक्षर करने के बाद विधेयक अधिनियम बन जाएंगे। असाधारण राजपत्र में प्रकाशित होते ही यह प्रदेश में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। उसके बाद ही प्रदेश में नई भर्तियों और स्कूल-कॉलेजों में दाखिले के लिए आरक्षण का रोस्टर जारी होगा।"

आबादी के आधार पर आरक्षण

इसके पहले सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि राज्य में जिस समुदाय की जितनी आबादी है, उसके हिसाब से ही आरक्षण तय किया गया है। न किसी को ज्यादा और ना किसी को कम। उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी क्वांटिफिएबल डाटा के साथ अपना पक्ष रखेगी। वहीं सदन में विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया। उनके विरोध के केंद्र में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी करने को लेकर भी था।

विरोध में रहे भाजपाई

अपने संबोधन में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सरकार कह रही है जनसंख्या के अनुपात को आरक्षण का आधार बनाया है तो बिना डाटा के कैसे आधार बना दिया। पहले डाटा पेश कर देते। फिर कानून बना लेते। सरकार को इतनी हड़बड़ी क्यों थी। वहीं भाजपा के एक अन्य वरिष्ठ सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आज का दिन संविधान के लिए काला दिन है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या छोटे से चुनाव के लिए संविधान के विरुद्ध कानून बनाए जाएंगे?

बहरहाल, विधानसभा ने बहुमत से आरक्षण संशोधन विधेयक और शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। अब देखना यह शेष है कि राज्य सरकार के इस पहल को राजभवन से कब मंजूरी मिलती है और यह भी कि इसे लेकर कोर्ट का रूख क्या होगा। ▪

सदस्यता रसीद

पत्राचार का पता : देशराज एडवोकेट, 12बी/284, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ (उ.प्र.) प्रतिशत मो.: 9415767238

मैं बसावन इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका के लिए सदस्यता ले रहा / रही हूं।

श्री / श्रीमती : ....

पता पिन कोड सहित : ....

मोबाईल नं. : .... ईमेल आईडी : ....

नगद राशि शब्दों में : ....

PhonePe

ACCEPTED HERE

☐ वार्षिक ₹ 300/- ☐ 2 वर्ष ₹ 500/- ☐ 5 वर्ष ₹ 1000/-

☐ 10 वर्ष ₹ 5000/- ☐ आजीवन ₹ 10,000/-

Bank Name	:	State Bank of India Main Branch, Azamgarh (U.P.)
AC Holder Name	:	Basavan India
AC No.	:	40640205456
IFSC Code	:	SBIN0000014

प्राप्तकर्ता का नाम हस्ताक्षर

Rate Card

Ad On Page	Rate	Colour/BW	Print Area
Full Page Front Inside	40,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back Cover	40,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back In Side	30,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	20,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	10,000/-	B/W	19 cm x 13cm
Quarter Page	10,000/-	Colour	123.5 Sqm
Quarter Page	5,000/-	B/W	123.5 Sqm
1/8 Page	5,000/-	Colour	61.75 Sqm
1/8 Page	3,000/-	B/W	61.75 Sqm

विज्ञापन के लिए संपर्क करें : +91 9415767238, +91 9453171770

बसावन नामा

आपके सामने प्रस्तुत है हमारे पिछले अंकों के बारे में हमारे सुधिपाठकों की प्रतिक्रिया जो कि हमारे पास विभिन्न माध्यमों से भेजी गई है।

मैंने बसावन इंडिया के सभी अंकों को पढ़ा है जिस वास्विकता के दर्शन में बसावन इंडिया के लेखों में देखा हैं। वैसा बहुत कम ही पत्रिकाओं में देखने को मिलता है। अपने इसी कलेवर के साथ बसावन इंडिया ने नए वर्ष में भी सामाजिक समस्याओं से अवगत कराती रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ बसावन की पूरी टीम को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं...

विजय कुमार सिंह
लखनऊ

मैंने कई पत्रिकाएं पढ़ी हैं। लेकिन बसावन इंडिया के तेवर और कलेवर जैसी पत्रिका आज के सन में नहीं दिखती है। समाज की समस्याओं का जिस वास्तुविकता के साथ चित्र बसावन में मिलता है शायद ही कहीं मिलता हो। बसावन ने पत्रकारिता का वो मापदंड स्थापित किया है जो पिछले कुछ सालों से कहीं खो गया था। बसावन इंडिया टीम को उसके लिए अद्भूत प्रयास के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

– खुशबू
अम्बेडकरनगर

समाज बटता जा रहा है एक स्तरीयकरण में जो समाज का निचला और पिछले पायदान पर है उसकी सुध लोग अपने लाभ के लिए ही लेते हैं। ऐसे दौर में बसावन इंडिया ने एक ऐसा मंच दिया है जहां से सभी को आवाज मिली है। एक भारतीय होने के नाते मै बसावन इंडिया के निष्पक्ष प्रयास के लिए उसका आभार मानती हूं।

– निकिता सिंह
आजमगढ़

जातीय जनगणना के विषय पर बसावन का प्रयास सराहनीय और उत्कृष्ट रहा है। मेरा संपादक जी से अग्रह है कि इस तरह का प्रयास जारी रखें।

– अभय कुमार, देवरिया

मैगजीन प्राप्ति के लिए संपर्क करें

देशराज एडवोकेट (लखनऊ)
9454411702

परिभाषा (दिल्ली एनसीआर)
8826063330

तेजबहादुर (भोपाल)
9406955327

कृष्णा पैकरा (अम्बिकापुर)
8839884273

संजीत बर्मन (बिलासपुर)
9754737875

श्री कोमल प्रसाद (कुशीनगर)
9565869539

राम सिंह यादव (आजमगढ़)
9415085600, 9454479600

अनिल दीप चौधरी (जौनपुर)
9554687948

प्रमोद कुमार (जौनपुर/खुटहन)
9506473500

प्रदीप चौहान (जौनपुर/सदर)
7985658300

प्रवीन कुमार (गाजीपुर)
9415888054

संजय कुमार (चंदौली)
9415978381

मनोज कुमार (सोनभद्र)
9005800506

विनय कुमार (बलिया)
9415659396

विजय कुमार (वाराणसी)
9506722313

अरविंद कुमार गदर (प्रयागराज झूसी)
7651961448

प्रयागराज में लक्ष्मी चौराहे पर हीना पुस्तक केंद्र पर भी उपलब्ध है।

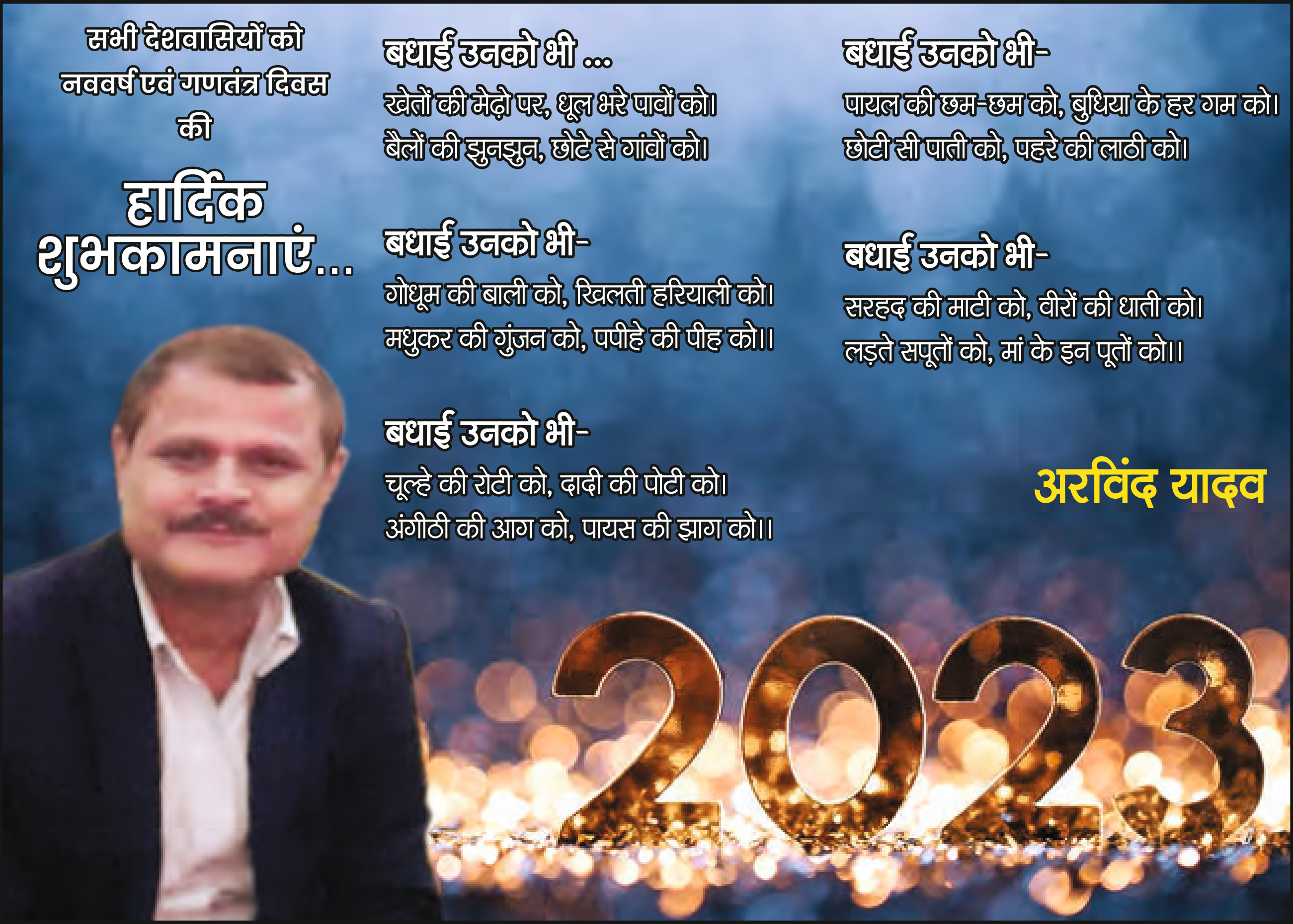

सभी देशवासियों को
नववर्ष एवं गणतंत्र दिवस
की
हार्दिक
शुभकामनाएं...
बधाई उनको भी ...
खेतों की मेढ़ो पर, धूल भरे पावों को।
बैलों की झुनझुन, छोटे से गांवों को।
बधाई उनको भी-
गोधूम की बाली को, खिलती हरियाली को।
मधुकर की गुंजन को, पपीहे की पीह को।।
बधाई उनको भी-
चूल्हे की रोटी को, दादी की पोटी को।
अंगीठी की आग को, पायस की झाग को।।
बधाई उनको भी-
पायल की छम-छम को, बुधिया के हर गम को।
छोटी सी पाती को, पहरे की लाठी को।
बधाई उनको भी-
सरहद की माटी को, वीरों की थाती को।
लड़ते सपूतों को, मां के इन पूतों को।।
अरविंद यादव
2023

राधा पुस्तक वाटिका
यू.जी.एफ-5, अनन्त टावर, पहाड़पुर, चौराहा,
कुर्सी रोड, जानकीपुरम, लखनऊ (उ.प्र.)
नर्सरी इण्टरमीडिएट तक
C.B.S.E., I.C.S.E. एवं
UP Board की किताबें
9532227400 | 9621931008 | 9935004236
स्टेशनरी व स्पोर्ट्स के थोक विक्रेता

जातीय जनगणना रिपोर्ट ग्राम सभा- छिड़ा, जिला- अमेठी

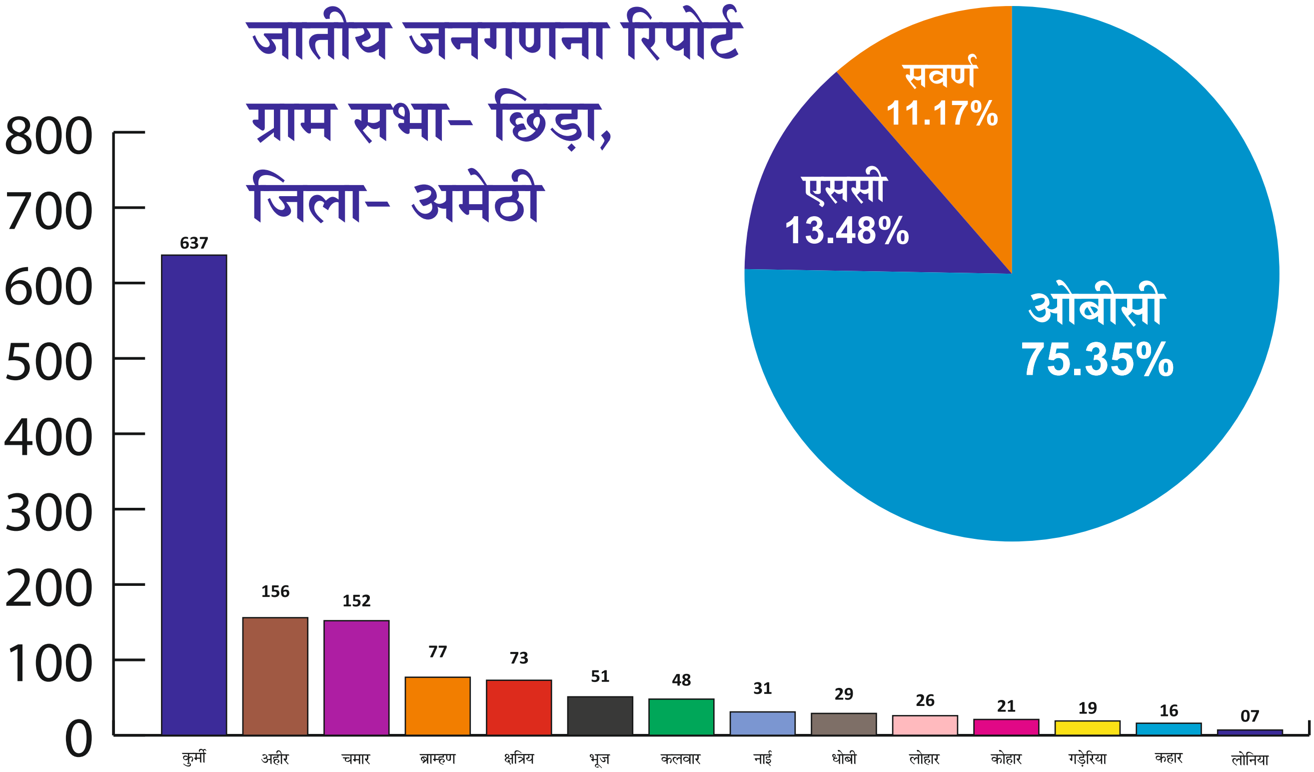

प्रस्तुत ग्राफ एवं पाई चार्ट के विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ 24 पढ़ें।

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में जातिवार संख्या

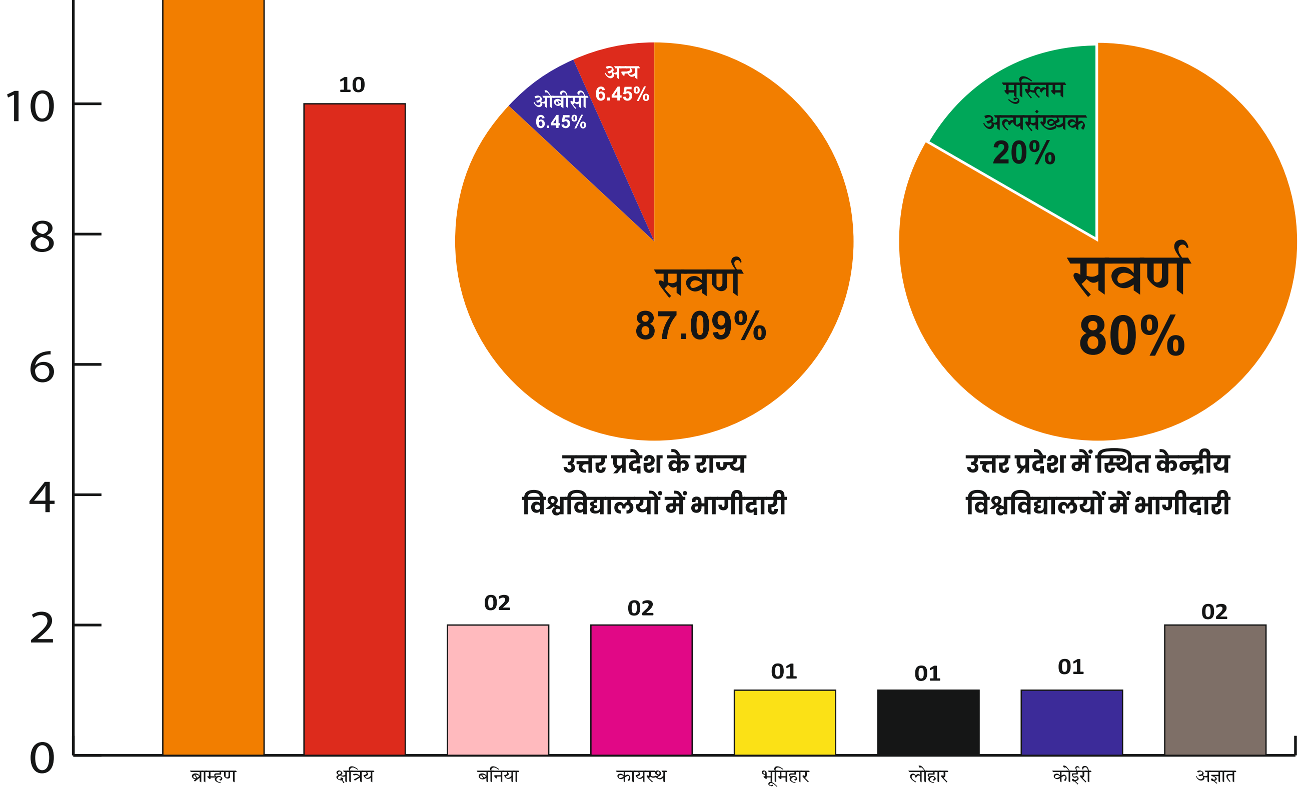

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में भागीदारी

उत्तर प्रदेश में स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भागीदारी

प्रस्तुत ग्राफ एवं पाई चार्ट के विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ 25 पढ़ें।